सितम्बर : 2024

वर्ष: 9 अंक: 9

मीडिया मैप

उदार जनतंत्र का सजग प्रहरी

अंग्रेजी की छाँव में हिंदी दिवस

शिक्षक दिवस का महत्व

शुल्क: 50

हम क्यों...

मीडिया मैप एक वैचारिक पत्रिका है। मीडिया जगत के नीतिपरक और मूल्यनिष्ठ बिन्दु तथा इनसे जुड़ाव रखने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मुद्दे इसकी विषयवस्तु है। मीडिया मैप की संपादकीय नीति उदारवादी, आधुनिक, प्रगतिशील व सर्वधर्म समभाव की भावना पर आधारित है। मीडिया मैप हमारे बहुलतावादी समाज की विविधताओं से सृजित समस्त सोच, विचार, दृष्टिकोण, मूल्य और मान्यताओं को अपने में समाहित करने का एक प्रयास है । हमारा उद्देश्य वैज्ञानिक सोच द्वारा समाज से जुड़े मूल मुद्दों पर एक प्रबुद्ध जनमत विकसित करना है जिससे देश में संकुचित मानसिकता और आपसी टकराव से उपर उठकर एक उच्चस्तरीय विचार-विमर्श का वातावरण तैयार हो सके।

मीडिया मैप

संपादकीय सलाहकार मंडल
डॉ. रामजीलाल जांगिड
डॉ बलदेवराज गुप्त
डॉ जॉन दयाल
डॉ गौहर रजा
मंगल सिंह आजाद

संपादक
प्रदीप माथुर

संयुक्त संपादक
सतीश मिश्रा

ब्यूरो प्रमुख
राजीव माथुर

मुख्य सह-संपादक
प्रशांत गौतम

सह-संपादक
अंकुर कुमार

विशेष प्रतिनिधि
जगदीश गौतम

विधि परामर्शदाता
संजय माथुर

पंजीकृत कार्यालय
2325, सेक्टर - डी , पॉकेट - 2 ,
वसंतकुंज , नई दिल्ली

कार्यालय
69 ज्ञानखंड-4 इंदिरापुरम
गाजियाबाद-201014

दूरभाष - 9810385757 / 9910069262

एम बी के एम फाउंडेशन प्रकाशन

ईमेल-
editor@mediamap.co.in

शिक्षक दिवस

हिन्दी दिवस

पत्र हमारे पाठको के		
एक झलक पिछले अंक की		
संपादकीय		
विचार प्रवाह		
राजनीतिक परिदृश्य		
लोकतंत्र में जनता के अधिकारों का हनन चिंताजनक	डॉ॰ सलीम ख़ान	9
स्वतंत्रता के 77 साल बाद भी धर्म और राजनीति की जंग जारी	जॉन दयाल	11
गठबंधन की राजनीति में फंसी मोदी सरकार	एन सत्यामूर्ति	12
आर्थिक जगत		
बैंकों में जमा राशि में गिरावट: अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट के संकेत	प्रो शिवाजी सरकार	13
भारत-बांग्लादेश संबंधों में उथल-पुथल का व्यापार पर गंभीर प्रभाव	प्रो शिवाजी सरकार	14
समसमयकी		
आज भी दलितों के लिए अच्छा जीवन एक सपना	प्रशांत गौतम	16
अंतरराष्ट्रीय		
क्या कनाडा में भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बनेगा	प्रभजोत सिंह	17
विविधा		
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के साथ बदलती नयी दुनिया कैसी होगी	प्रशांत गौतम	19
महिला संसार		
मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार और सरकार की खामोशी	डॉ. सलमान अरशद	21
कमला हैरिस पर अपमानजनक टिप्णी	इंदु रानी सिंह	22
स्वास्थ्य जगत		
होम्योपैथिक उपचार करके डेंगू से खुद को बचाएं	डॉ नवल कुमार वर्मा	23
कथा साहित्य		
माँ की ममता का मारा एक खूंखार डाकू	दिनेश वर्मा	26
पुस्तक समीक्षा:		
व्यंग्य संग्रह "दस हाथ वाला आदमी"	हुकम सिंह	28
मिथकों से विज्ञान के सफर के अनबूझे रास्ते	डॉ मुज़फ्फर हुसैन ग़ज़ाली	29
मीडिया/फ़िल्में		
मोदी के शासनकाल में उपेक्षित मीडिया	डॉ. सतीश मिश्रा	32
कोविड-19 के समय आर्थिक तंगी में धकेले गये पत्रकार	मीडिया मैप न्यूज़	34
हिंदी दिवस		
हिंदी के साथ अंतरराष्ट्रीय खिलवाड़	अनूप श्रीवास्तव	36
हास्य व्यंग		
हिंदी भाषा का कटोरा !	अनूप श्रीवास्तव	37

पत्र हमारे पाठको के

गोपाल मिश्रा - अद्‌भुत। राष्ट्रीय मुद्दों पर बेबाक चर्चा के लिए सभी साथी बधाई के पात्र है। इससे यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि आज भी पत्रकारिता के आदर्श कायम ही। इसलिए मीडिया मैप का महत्व और भी अधिक हो जाता है।

डॉ रमेश दीक्षित - बहुत ही बढ़िया पत्रिका निकाली है आपने. आपका राजीव गांधी पर और सतीश का बांग्लादेश पर लेख अच्छे लगे।

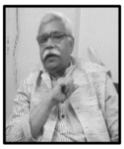

एक झलक पिछले अंक की

राजीव गाँधी जो भितरघात के शिकार हुए :

वर्ष 1984-85 में अप्रत्याशित जनसमर्थन प्राप्त कर भारत का प्रधानमंत्री बन कर राजीव गांधी भारतीय राजनीति के क्षितिज पर बहुत तेजी से उभरे थे। जितनी तेजी से राजीव गांधी का उदय हुआ उतनी ही तेजी से तीन वर्षों के अंदर उनका पतन भी होना प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी हत्या हुई। पर उनकी राजनैतिक हत्या का प्रयास तो वर्ष 1987 में बोफोर्स घोटाले के खुलासे के साथ ही किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या वर्ष 1987 में उनकी राजनैतिक हत्या और फिर 1991 में उनकी शारीरिक हत्या स्वाभाविक थी या उसके पीछे कोई राजनैतिक षड़यंत्र था। -***प्रो प्रदीप माथुर***

पेरिस ओलंपिक्स में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन:

प्रधानमंत्री के राज में दिन रात भारत के विश्व गुरु होने का दम भर जाता है। ना जाने मोदी का भारत किस क्षेत्र में विश्व गुरु है पर जहां तक पेरिस ओलिंपिक का सवाल है वह किसी मोहल्ले के गुरु का फिस्सडी विद्यार्थी ही लगा। 1.4 अरब लोगों का एक राष्ट्र, जो स्वयं को विश्व आर्थिक शक्ति होने का दावा करता है, 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों में अपना अभियान खेलों में विश्व चैंपियन बनने के करीब भी नहीं पहुंच पाया। - ***प्रभजोत सिंह***

चुनाव के बाद नए अवतार के रूप में उभरे राहुल गाँधी:

राहुल गाँधी ने विपक्ष के नेता की हैसियत से अपने पहले सम्बोधन में बीजेपी को धराशायी कर दिया। राहुल गाँधी अगर मणिपुर, महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर भाषण देते तो लोग कहते, यह तो बीजेपी का घर ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री उसमें नहीं रहते, मगर वह तो हिन्दुत्व के दरबार में घुस गए। बीजेपी यह कहकर वरग़लाती है कि फ़ुलाँ-फ़ुलाँ हिन्दुत्व के दुश्मनों की वजह से हिंदू धर्म ख़तरे में है। हम उनसे सनातन धर्म की हिफ़ाज़त करते हैं। इस सेवा के बदले हमें वोट देकर सत्ता में रखा जाए। राहुल गाँधी ने आगे बढ़कर कह दिया चूँकि हिंदू धर्म हिंसा की शिक्षा नहीं देता इसलिए यह अपने आपको हिंदू कहकर दिन-रात नफ़रत-नफ़रत, हिंसा-हिंसा फैलानेवाले सिरे से हिंदू ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने देखा कि राहुल ने हिन्दुत्व पर ही हाथ मार दिया तो सोचा कि अगर यही छिन जाए तो मैं किस बुनियाद पर हुकूमत करूँगा? बस फिर क्या था। इस नाज़ुक रग पर हाथ रखते ही वह बिलबिला उठे और राहुल के जाल में फँस गए। - ***डॉ सलीम खान***

बजट: क्या विकास का लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा?:

वित्त मंत्री द्वारा 23 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में दीर्घकालिक विकास का दृष्टिकोण है - जिससे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिर भी, गरीबों, किसानों, असंगठित श्रमिकों, एसएमई, युवाओं और गृहिणियों की जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है। 144 करोड़ लोगों के लिए 48 लाख करोड़ रुपये के बजट की कुछ प्रमुख विशेषताएं राजकोषीय समेकन, पूंजीगत व्यय, कौशल विकास, प्राकृतिक खेती और फसल उत्पादकता, हरित निवेश और अनुसंधान, सभी के लिए आवास और कर व्यवस्था का सरलीकरण हैं। - ***प्रो लल्लन प्रसाद***

संपादकीय

शिक्षा का आधार शिक्षक: उनकी समस्याओ का समाधान आवश्यक

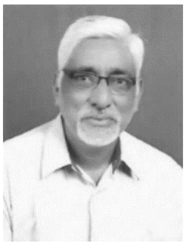

प्राचीन काल से ही हमारे समाज में शिक्षा देने वाले गुरु का स्थान सर्वोपरि रहा है। मध्ययुगीन भारत के संत कवि कबीर दास ने गुरु को भगवान से भी पहले माना है, क्योंकि वह कहते हैं कि बिना गुरु के भगवान तक पहुँचना संभव नहीं है। आज भी हमारे देश के आम जनमानस के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव है। हालांकि नए समाजिक आर्थिक परिवेश में ना तो समाज के अधिक प्रतिमाशाली लोग अध्यापन के क्षेत्र में जा रहे हैं और ना ही समाज में उनका स्थान उतना महत्त्वपूर्ण रहा है।

स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का प्रसार तेजी से हुआ। प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के कार्यकाल में वर्ष 1986 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। आज भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने वाले एक करोड़ से अधिक शिक्षक और 20 करोड़ से अधिक विद्यार्थी हैं जो भारत को शिक्षा की एक विश्व महाशक्ति बनाते है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओ की भागेदारी बहुत है और पुरुष अध्यापकों की तुलना में महिला शिक्षकों का अनुपात अधिक है।

पर इन सब बातों के साथ साथ हमारा शिक्षक समुदाय कई समस्याओं का शिकार है और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम देश के समुचित सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास के लिए इन समस्याओं पर तुरंत ध्यान दें और उनके समाधान की दिशा मे कार्यरत हो।

सबसे बड़ी समस्या अध्यापकों के सही चयन और वेतन मान की है। यह दुख की बात है कि अध्यापकों के चयन जैसे पवित्र काम मैं आज भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, जातिवाद तथा घूसखोरी का बोलबाला है। इसके कारण योग्य प्रतिभावान और अध्ययन-अध्यापन में सच्ची रुचि रखने वाले तमाम लोग शिक्षक बनने से वंचित रह जाते हैं। मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के शासन में आरएसएस-भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) पृष्ठभूमि के लोगों का ही सरकारी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थानों तथा स्कूलों में चयन हुआ और इससे शिक्षा क्षेत्र को बहुत हानि हुई क्यों इस वैचारिक पृष्टभूमि से न आनेवाले तमाम लोग अध्यापन के दायरे से बाहर हो गए।

शिक्षकों से जुडी दूसरी बड़ी समस्या शिक्षा का तेजी से बढ़ता व्यवसायीकरण है। शिक्षा का आर्थिक लाभ को व्यापार बनाने के कारण उसमे चकाचौंध का वातावरण देना आव्यशक हो गया है। इस चकाचौंध का प्रभाव शिक्षकों के चरित्र पर भी पड़ा है। गंभीर अध्ध्यन द्वारा जनित ज्ञान पिपासा ,गरिमा ,विनम्रता और आत्मचिंतन जैसे जीवन मूल्यों के स्थान पर अध्यापक , विशेषता महिला अध्यापिकाएँ आधुनिक जीवनस्तर प्रदर्शनवाद तथा शिक्षा विक्रेता के रूप में अधिक सक्रिय दिखाई देते हैं।

शिक्षा के व्यवसायीकरण ने जहाँ शिक्षकों के आर्थिक शोषण को प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है वहीं उनके ऊपर काम का बहुत अधिक बोझ डाल दिया है। इसके कारण उनको स्वाध्याय का समय मिलना कम हो गया है, जो एक शिक्षक के बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है।

हमारे समाज और विशेषत: सरकार को शिक्षकों की समस्याओं के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और लोकलुभान नीति तथा दिखावटी लेखापढ़ी से ऊपर उठकर शिक्षकों की वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिए। शिक्षा का फैलाव अच्छी बात है लेकिन जब तक उसके मूल आधार शिक्षकों की समस्याओ पर ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक न तो शिक्षा का गुणात्मक विकास होगा न ही हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति संभव होगी । आवश्यक है की अध्यापक दिवस के अवसर पर हम इस बात को पूरी गंभीरता से समझे ।

प्रदीप माथुर

मातृभाषा की उपेक्षा करते यह पब्लिक स्कूल

हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो हमें अपनी मातृभाषा हिंदी के महत्व को याद दिलाता है। हालांकि, आज के समय में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा, जिसकी वह हकदार है। यह स्थिति सिर्फ हमारी भाषा के लिए नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन चुकी है।

आज के दौर में अंग्रेजी का प्रभाव हर जगह महसूस हो रहा है, और ऐसे में यह सवाल उठता है कि हिंदी का स्थान क्या है? खासकर स्कूलों में, जहां बच्चों की शिक्षा और संस्कारों की नींव रखी जाती है। शिक्षा का माध्यम किसी भी बच्चे की सोच और समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन हिंदी की उपेक्षा स्कूलों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।

बीते कुछ दशकों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इन स्कूलों का उद्देश्य अंग्रेजी में शिक्षा देना है, जो अपने आप में गलत नहीं है। लेकिन हिंदी की उपेक्षा चिंताजनक है। कई स्कूलों में हिंदी बोलने पर जुर्माना तक लगाया जाता है, जिससे बच्चों को केवल अंग्रेजी में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इस स्थिति का सबसे बड़ा असर बच्चों पर पड़ता है। वे अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं और हिंदी उनके लिए बोझ बनती जा रही है। वे अंग्रेजी को सफलता और उन्नति का प्रतीक मानते हैं, जबकि हिंदी को कमतर समझते हैं। हालांकि, अंग्रेजी की वैश्विक भाषा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी मातृभाषा को भुला दें।

अंग्रेजी स्कूलों की लोकप्रियता के पीछे अभिभावकों की सोच भी एक बड़ा कारण है। ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में दाखिला दिलाना चाहते हैं, मानकर कि इससे उनके बच्चे समाज में सम्मान प्राप्त करेंगे और बेहतर करियर की संभावनाएं बढ़ेंगी। यह सोच आंशिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन भी है।

हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। हालांकि, आज की शिक्षा प्रणाली, विशेषकर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में, हिंदी को वह सम्मान नहीं मिल रहा, जिसकी वह हकदार है।

हर साल हिंदी दिवस पर भाषण और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन क्या इससे स्थिति में बदलाव आता है? क्या हिंदी को वह मान-सम्मान मिल रहा है, जिसका वह हकदार है?

आज के वैश्विक युग में अंग्रेजी का महत्व बढ़ गया है, यह व्यापार, विज्ञान, तकनीक और वैश्विक संचार की भाषा बन गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएं। हिंदी हमारी जड़ों और संस्कृति का आधार है।

हमें हिंदी और अंग्रेजी के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। अंग्रेजी सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी मातृभाषा को नकारना नहीं। स्कूलों को हिंदी के महत्व को समझाना चाहिए और बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि किसी भी भाषा को सीखना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा को भूलना हमारी संस्कृति से दूर होने के समान है।

सरकार और शिक्षा नीति-निर्माताओं को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। नई शिक्षा नीति में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के महत्व को बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू करने की जरूरत है।

अभिभावकों को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि अंग्रेजी सीखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी अपनी मातृभाषा को जानना और समझना है। बच्चों को दोनों भाषाओं में समान रूप से पारंगत बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।

अंग्रेजी स्कूलों की बढ़ती संख्या और हिंदी की उपेक्षा एक गंभीर मुद्दा है। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारी मातृभाषा हमारी पहचान और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इसे संजोना और सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। ***(अंकुर कुमार)***

बहन मायावती के बदलते तेवर

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती, जो उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बढ़ते प्रभाव और दबाव के बीच, उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। यह साफ दिख रहा है कि वह भाजपा के प्रति नरम रवैया अपनाए हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में आगामी 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए, मायावती का यह रवैया समझा जा सकता है। भाजपा इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है, खासकर 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद से उसकी स्थिति कमजोर हुई है।

हाल ही में, मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर यह साफ किया कि वह सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं रखतीं। उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के बहुजन आंदोलन के प्रति अपनी आजीवन प्रतिबद्धता व्यक्त की। मायावती ने कहा कि वह अपने जीवन की अंतिम सांस तक दलित आंदोलन के लिए काम करती रहेंगी और विरोधियों की साजिशों को नाकाम करेंगी।

हालांकि, मायावती पिछले कुछ समय से सार्वजनिक जीवन में कम नजर आती हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया पर अचानक से सक्रिय होने के पीछे भी उपचुनावों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। इन चुनावों से भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्थिति पर बड़ा असर पड़ेगा।

मायावती की बसपा ने पिछले कुछ चुनावों में खराब प्रदर्शन किया है, लेकिन इसके बावजूद, उनके वोट अक्सर भाजपा के पक्ष में जाते हैं क्योंकि वे विपक्षी पार्टियों, विशेष रूप से सपा और कांग्रेस के वोट शेयर में कटौती करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इसका उदाहरण देखने को मिला था।

मायावती ने 1995 के कुख्यात लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए भाजपा की सराहना की, जिन्होंने उस समय उनकी जान बचाई थी। इसके विपरीत, उन्होंने कांग्रेस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।

जाति जनगणना की मांग को लेकर भी मायावती ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर दबाव डाला है, ताकि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अधिकार सुरक्षित रह सकें। ***(सतीश मिश्रा)***

कमला हैरिस अर्थव्यवस्था का कॉर्पोरेट विरोधी रुख

कमला हैरिस, अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, यदि अपने साहसिक आर्थिक एजेंडे को लागू करने में सफल होती हैं, तो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य बदल सकता है। उनका उद्देश्य है कॉर्पोरेट शक्ति पर नियंत्रण और जीवन की लागत को कम करना। इससे भारत जैसे देशों को भी अपने मौजूदा आर्थिक मॉडल पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, जैसा कि उदारीकरण के दौर में हुआ था।

हैरिस का संदेश साफ है: अमेरिकी अब बढ़ती कीमतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके आक्रामक लोकलुभावन एजेंडे का मकसद वैश्विक आर्थिक नीतियों को भी प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी लोग महंगाई और बढ़ते

खर्चों के कारण प्रगति महसूस नहीं कर रहे हैं। भोजन, किराया, गैस, और दवाओं की बढ़ती कीमतें आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। यह भारत की वर्तमान स्थिति से भी मेल खाता है, जहाँ असमानता और बेरोजगारी चरम पर है।

भारतीय कॉर्पोरेट शक्तियों पर हैरिस की नज़रें हैं, क्योंकि भारत में बड़े कॉर्पोरेट्स को कर छूट और अन्य आर्थिक सुविधाएँ दी जा रही हैं। अमेरिकी एंटी-ट्रस्ट कानूनों की तुलना में, भारतीय नीतियाँ कॉर्पोरेट्स के लिए अधिक अनुकूल मानी जाती हैं। भारत में पूंजीगत लाभ कर और किराये को लेकर चर्चा हो रही है, और हैरिस चाहती हैं कि कॉर्पोरेट मकान मालिक किराया बढ़ाने के लिए अनुचित तरीकों का उपयोग न करें।

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी अमेरिका की स्थिति खराब है, और हैरिस ने स्वास्थ्य ऋण खत्म करने और दवाओं की कीमतें सीमित करने का वादा किया है। भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा खर्चों को लेकर चिंता बढ़ रही है। हालाँकि, भारत ने पीएम जन औषधि जैसी योजनाओं के जरिए सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने में बेहतर प्रदर्शन किया है।

हैरिस के आर्थिक प्रस्तावों में परिवारों को बाल कर क्रेडिट देना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ शामिल हैं। यह भारत की प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं से प्रेरित है, जो गरीबों और किसानों को राहत देने में सफल रही हैं।

हैरिस का आर्थिक दृष्टिकोण एक मजबूत समाजवादी रुख दिखाता है, जो भारतीय बजट से काफी कुछ उधार लेता है। अब भारत की बारी है कि वह कॉर्पोरेट शक्तियों पर नियंत्रण करके गरीबों और मजदूर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करे ***(शिवाजी सरकार)***

दुनियाभर में बिखरी भारतीय आमों की मिठास

भारत ने 2024 के सत्र में आम निर्यात के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस वर्ष भारत ने करीब 2.5 लाख टन आमों का निर्यात किया, जिससे देश को लगभग 4,500 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है। अल्फांसो, दशहरी, केसर और लंगड़ा जैसे भारतीय आम दुनियाभर में मशहूर हैं और इनका निर्यात भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। आम की खेती न केवल किसानों को आर्थिक समृद्धि देती है, बल्कि देश की वैश्विक छवि को भी सशक्त करती है।

भारत को "आमों का राजा" कहा जाता है, और यह विश्व के सबसे बड़े आम उत्पादकों में से एक है। भारतीय आम अपनी मिठास, अनोखे स्वाद और विविधता के कारण दुनियाभर में पसंद किए जाते हैं। आम के निर्यात से भारतीय कृषि उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय मांग भी बढ़ रही है। यह सफलता भारतीय किसानों की मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने अपनी निष्ठा से भारत को वैश्विक आम बाजार में मजबूत किया है।

आम का मौसम आते ही इसकी मिठास और सुगंध लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। देशभर में विभिन्न स्थानों पर मैंगो फेस्टिवल का आयोजन होता है, जहां आम प्रेमी अपनी पसंद के आमों का आनंद लेते हैं। लखनऊ, दिल्ली, आगरा और अन्य शहरों में ऐसे महोत्सव विशेष रूप से लोकप्रिय होते हैं।

आम को 'फलों का राजा' यूं ही नहीं कहा जाता। मुगल बादशाहों से लेकर नवाबों और शायरों तक, सभी इसकी मिठास के दीवाने रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में स्थित हाजी कलीम उल्लाह खान द्वारा विकसित एक विशेष पेड़ पर 300 से अधिक किस्मों के आम उगते हैं, जिससे वह 'मैंगो मैन' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इस पेड़ पर कई मशहूर हस्तियों के नाम पर आम की किस्में विकसित की हैं।

उत्तर प्रदेश में दशहरी, चौसा, लंगड़ा और सफेदा जैसी प्रमुख किस्मों के आम पाए जाते हैं। दशहरी आम की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के दशहरी गाँव से हुई है, जहां 200 साल पुराना "दशहरी का मदर ट्री" आज भी मौजूद है। इस पेड़ की कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं।

भारतीय आम की यह विविधता और समृद्धि भारत को वैश्विक आम बाजार में विशेष स्थान दिलाती है, जिससे हर साल नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। ***(ज़ेबा हसन)***

राजनीतिक परिदृश्य

लोकतंत्र में जनता के अधिकारों का हनन चिंताजनक

डॉ॰ सलीम ख़ान

ठंडा मतलब कोका कोला’ और ‘कोलगेट यानी टूथपेस्ट’ की तरह लोकतंत्र से भी ऐसी बहुत सारी आशाएँ जोड़ दी गई हैं कि जिनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मसलन जब न्याय और इंसाफ़ को ख़तरा होता है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटा जाता है तो इसे लोकतंत्र के लिए घातक माना जाता है, हालाँकि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी जानेवाली सरकार को इस अत्याचार का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी की एमरजेंसी को उचित ठहराना न्यायपालिका की मजबूरी थी और अगर नरेंद्र मोदी भी उसे लागू कर दें तो वह कार्रवाई इंसानियत के ख़िलाफ़ होने के बावजूद लोकतंत्र विरोधी नहीं होगी, क्योंकि इस राजनैतिक व्यवस्था में जनता के कल्याण के नाम पर जनता की ख़ातिर जनता के द्वारा चुनी जानेवाली सरकार को अपनी मन-मानी करने की पूरी आज़ादी है। संसद भवन में क़ानून बनाकर सुप्रीमकोर्ट के चीफ़ जस्टिस को चुनाव आयोग से निकाल बाहर किया जाए तब भी वह बेचारा कुछ नहीं कर सकता। योगी अगर ‘लव जिहाद’ के लिए उम्र क़ैद की सज़ा प्रस्तावित कर दे तो न्यायपालिका उसके अनुसार फ़ैसला करने पर मजबूर होगी तथा प्रशासन उसे लागू करने का पाबंद होगा।

लोकतंत्र की खामियों पर चिंतन

लेख में लोकतंत्र की विडंबनाओं पर गहराई से चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे जनता द्वारा चुनी गई सरकार को अपने हितों के नाम पर मनमानी करने का अधिकार मिलता है। न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसे संस्थान भी कभी-कभी इन धांधलियों के सामने असहाय नजर आते हैं। चुनावों में अनियमितताएँ होने के बावजूद, जनता और मीडिया में इसके खिलाफ आवाज उठाने की कमी देखी जा रही है।

दुनिया के एक बड़े लोकतंत्र अमेरिका से लेकर बुद्धिमान लोकतंत्र इस्राईल में भी इस तरह के बेलगाम तरीक़े से क़ानून बनाए जाते रहते हैं और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत भी पीछे नहीं है। भारत को इस बात पर बड़ा गर्व है कि बहुत सारी नैतिक एवं सामाजिक बुराइयों के बावजूद यहाँ कोई फ़ौजी बग़ावत नहीं हुई और चुनावी प्रक्रिया के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण होता रहा, हालाँकि मुंबई की नगरपालिका के चुनाव पिछले साढ़े सात साल से मात्र इसलिए नहीं हुए, क्योंकि बीजेपी की सफलता की सम्भावना नहीं है। जम्मू-कश्मीर में दस साल पहले चुनाव हुए थे। सुप्रीमकोर्ट ने सितंबर के अन्त तक चुनाव करवाने की पाबंदी लगाई, फिर भी कोई हलचल दिखाई नहीं देती। एक राज्य और शहर को अपवाद मान लिया जाए तब भी चुनाव के दौरान शोर-शराबा आम-सी बात है। उत्तरप्रदेश के पंचायत चुनाव में तो कैमरे के सामने उम्मीदवारों का अपहरण और महिला उम्मीदवार से दुर्व्यवहार तक हुआ, लेकिन दोबारा वोट नहीं पड़े। इन सारी ज़्यादतियों को तमाम सुबूतों के बावजूद जायज़ और अच्छा समझा गया, क्योंकि वह विपक्ष की मर्ज़ी और मंशा के अनुसार था, लेकिन अब तो चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता भी सन्देहों के घेरे में है।

पिछले दिनों एडीआर और वीएफ़डी की दो चौंकानेवाली रिपोर्टों में चुनावी धाँधली को सुबूतों सहित बेनक़ाब किया गया, मगर किसी के कान पर जूँ भी नहीं रेंगी। इससे पता चलता है कि जनता वोट देने की अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर देने के बाद परिणामों के प्रति उदासीन हो जाती है। उसके फ़ैसले पर अगर कोई डाका डालकर उसे चुरा ले तो भी किसी को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्ज़ (एडीआर) भारतीय राजनीति और चुनाव प्रक्रिया पर नज़र रखनेवाली एक प्रतिष्ठित संस्था है। इसके प्रमुख प्रोफ़ेसर जगदीप छोकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह रहस्योद्घाटन किया कि राष्ट्रीय चुनावों के दौरान 538 लोकसभा सीटों पर कई अन्तर्विरोध पाए गए। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि 2019 के चुनावों में भी कई सीटों पर मतभेद सामने आए थे, मगर उनकी संख्या केवल 347 थी। इस संख्या में अबकी बार असाधारण वृद्धि हुई और वह बढ़कर 538 पर पहुँच गई। यह आश्चर्यजनक आंकड़े हैं, क्योंकि इस तरह के अन्तर्विरोध के आधार पर सन्दिग्ध होनेवाली सीटें 99 प्रतिशत को पार कर जाती हैं। उक्त रिपोर्ट के अनुसार फ़ाइनल आंकड़े जारी करने में असाधारण देर, चुनाव क्षेत्र और पोलिंग स्टेशनों की ओर से आंकड़ों का अन्तर्विरोध तथा चुनाव परिणामों के एलान में फ़ाइनल आंकड़ों का आधार ऐसे कारक थे जिनकी बाबत आम लोगों के मन-मस्तिष्क में चिन्ता पैदा हुई है।

चुनावी धांधली पर रिपोर्ट

एडीआर और वोट फ़ॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्टों ने 2024 के लोकसभा चुनावों में व्यापक धांधली के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 538 लोकसभा सीटों पर वोट गिनती में अन्तर्विरोध सामने आए, जो पहले से कहीं अधिक हैं। इसमें कई सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों की संख्या में असमानता पाई गई, जिससे चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं।

एडीआर की जाँच रिपोर्ट कोई राजनैतिक हवाबाज़ी नहीं है। इसमें दावा किया गया है कि 362 लोकसभा सीटों पर जो वोट डाले गए थे उनके मुक़ाबले गणना किए जानेवाले वोटों की संख्या 5 लाख 54 हज़ार

598 वोट कम है। सवाल यह है कि वोट कहाँ चले गए और किसके इशारे पर ग़ायब किए गए? इस बार 176 सीटें ऐसी हैं जहाँ कुल 35 हज़ार 93 ज़्यादा वोटों की गिनती हुई है। ये वोट कहाँ से और क्यों आए? ये सवालात भी महत्त्वपूर्ण हैं। रिपोर्ट के अनुसार केवल 195 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जिनपर डाले गए और गिने जानेवाले वोटों की संख्या में कोई फ़र्क़ नहीं है। 2019 में भी ऐसे फ़र्क़ मौजूद थे, जिनमें कम से कम 1 वोट से लेकर सबसे ज़्यादा 1 लाख 1323 वोटों तक का फ़र्क़ था। यह अन्तर मामूली नहीं, बल्कि कुल वोटों का 10.49 प्रतिशत था।

राज्य स्तर पर जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है राजधानी दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर 8159 कम वोटों की गिनती हुई और उत्तराखंड की 5 सीटों पर 6315 कम वोट गिने गए। इन दोनों स्थानों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया यानी विपक्ष का सूपड़ा साफ़ हो गया, मगर एडीआर की रिपोर्ट यूपी की 55 सीटों का भी ज़िक्र करती है जहाँ डाले गए वोट की तुलना में 53960 वोट कम गिने गए, उसके बावजूद बीजेपी अपनी नैया को डूबने से नहीं बचा सकी, जबकि 25 सीटें ऐसी भी हैं जहाँ 6124 वोट ज़्यादा गिने गए। सवाल यह है कि अब तो सारा काम मशीन से होता है, ऐसे में फ़र्क़ क्या अर्थ रखता है? झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर 26342 कम वोटों की गिनती हुई। दो सीटें ऐसी हैं जिनपर कुल मतदान के मुक़ाबले 393 वोट ज़्यादा गिने गए। उसके अलावा बिहार की कुल 40 सीटों में से 21 सीटों पर 5015 वोटों की ज़्यादा गिनती हुई, जबकि 19 सीटों पर कुल वोटों से 9924 वोट कम गिने गए। यह चिन्ताजनक आंकड़े चौंकानेवाले हैं।

एडीआर की रिपोर्ट से पहले 'वोट फ़ॉर डेमोक्रेसी ने कंडक्ट ऑफ़ लोकसभा चुनाव 2024' नामक विश्लेषण पेश किया। वोट फ़ॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट ने भी लोक सभा 2024 के चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के अनुसार ख़ुद चुनाव आयोग के द्वारा आरम्भिक वोटिंग के आंकड़ों से फ़ाइनल वोटिंग के आंकड़ों तक कुल 4.65 करोड़ वोटों की हेराफेरी हुई है। इसकी वजह से बीजेपी के नेतृत्ववाली एनडीए को देश के 15 राज्यों में 79 सीटों का फ़ायदा हुआ। यह संख्या अगर एनडीए निकालकर इंडिया गठबन्धन की झोली में डाल दी जाए तो देश का राजनैतिक परिदृश्य बिल्कुल बदल जाता है। इससे ज़ाहिर होता है कि मानो चुनाव परिणाम को अपहृत करके अपने पक्ष में कर लिया गया है, लेकिन इस

रिपोर्ट के सार्वजिक होने के बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर पूरी तरह चुप्पी छाई रही। कहीं भी कोई बहस दिखाई नहीं देती, हर तरफ़ भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि इन पत्रकारों के एक ओर चैनल का मालिक यानी शिकारी दाना-पानी लेकर बैठा है और दूसरी तरफ़ सरकारी जल्लाद नंगी तलवार लेकर खड़ा है। इन दोनों को ख़ुश रखने के लिए पत्रकार लोगों को साक़िब लखनवी के शेर पर थोड़े से संशोधन के साथ अमल करना पड़ता है—

मीडियावालो वतन में यूँ गुज़ारा चाहिए
बाग़बाँ भी ख़ुश रहे राज़ी रहे सय्याद भी

वोट फ़ॉर डेमोक्रेसी के द्वारा चुनाव परिणाम और वोटर टर्न आउट के आंकड़ों के विश्लेषण में चुनाव आयोग के द्वारा आरम्भिक वोटिंग से फ़ाइनल वोटिंग के आंकड़ों तक सात चरणों में सभी चुनाव क्षेत्रों के अंदर 3.2 % से 6.32 % तक का फ़र्क़ रिकार्ड किया गया। इसकी रौशनी में वोट प्रतिशत का फ़र्क़ आँध्र प्रदेश में 12.54 % और ओडिशा में 12.48 % तक पहुँच गया। इन दोनों राज्यों में राज्य चुनाव भी साथ हुआ और सरकार बदल गई यानी बीजेपी की अपनी या उसके गठबन्धन मित्र की सरकार बन गई जो उसके लिए बैसाखी का काम कर रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सत्ताधारी मोर्चा यानी एनडीए को वोटिंग प्रतिशत में दरमियान में होनेवाली वृद्धि से फ़ायदा हुआ है। इस असाधारण वृद्धि के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्ववाली एनडीए को देश भर में 79 अतिरिक्त सीटें मिलीं। उनमें ओडिशा से 18, महाराष्ट्र से 11, पश्चिम बंगाल से 10, आँध्र प्रदेश से 7, कर्नाटक से 6, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से 5, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से 3, असम और अरुणाचल प्रदेश की दो सीटें शामिल हैं। गुजरात जैसे सुरक्षित राज्य में काँग्रेस को खाता खोलने से रोकने के लिए और केरल में अपना खाता खोलने की ख़ातिर एक-एक सीट पर यह खेल खेला गया। इस तरह चोर दरवाज़े से क़ायम होनेवाली सरकार अब बजट के द्वारा जनता की जेब पर डाका डाल रही है। ऐसे में देश के मतदाताओं की ज़बान पर अपने प्रधानमंत्री के लिए (मजरूह सुलतानपुरी से शमा याचना सहित) यह गुहार है—

चुरा लिया है तुमने इलेक्शन, बजट नहीं चुराना सनम
बदल के तुम अपनी ही गारंटी, कहीं बदल न जाना सनम

राजनीतिक परिदृश्य

स्वतंत्रता के 77 साल बाद भी धर्म और राजनीति की जंग जारी

डॉ जॉन दयाल

स्वतंत्रता के बाद से भारत ने एक लंबा सफर तय किया है, जहां धर्मों की भूमिका और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे लगातार चर्चा का विषय रहे हैं। 1947 में आजादी मिलने के बाद, देश ने न केवल अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की, बल्कि विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के प्रयास भी किए।

भारत 77 वर्षों से एक स्वतंत्र राष्ट्र है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को अपने ऐतिहासिक भाषण में भारत के भविष्य के लिए एक नई उम्मीद जगाई थी। स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और अपनी पहचान को स्वीकार करना भी है। यह समझना कि अब हम अपनी नियति के निर्माता हैं, एक सशक्तिकरण का प्रतीक है।

ईसाइयों के लिए, स्वतंत्रता ने धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी आकार दिया। उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए, अन्य आस्थाओं के प्रति सम्मान विकसित किया। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, धार्मिक विभाजन और घृणा की राजनीति ने समाज में हिंसा और असंतोष को जन्म दिया है।

> ***बौद्ध और ईसाई धर्म का संघर्ष और अस्तित्व***
>
> *बौद्ध और ईसाई धर्मों का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। बाबासाहेब अंबेडकर के नेतृत्व में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बना। वहीं, ईसाई धर्म, जो अक्सर औपनिवेशिक शासन से जोड़ा जाता है, को भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान को स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा है।*

राजनीतिक हिंदुत्व के उदय के साथ, कुछ विचारधारात्मक समूहों ने देश के भूगोल को अपनी धार्मिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ने की कोशिश की है। इस प्रयास में उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति विभाजनकारी नीति अपनाई, जिससे समाज में असहमति और हिंसा की स्थिति बनी।

विडंबना यह है कि जो लोग धर्म के नाम पर राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद कर रहे हैं, उनके पास स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। स्वतंत्रता के बाद का भारत एक ऐसा गणराज्य है, जहां समानता और अधिकारों की गारंटी देने वाला संविधान है। लेकिन, कुछ समूहों ने इन अधिकारों को कमजोर करने के प्रयास किए हैं।

भारत में बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म का एक लंबा इतिहास रहा है। बौद्ध धर्म, जो कि देश में कभी प्रमुख धर्म था, अब केवल कुछ क्षेत्रों में ही पाया जाता है। तिब्बती बौद्ध, जो चीन से भागकर भारत आए, अब तीसरी पीढ़ी के रूप में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक में रह रहे हैं। वहीं, देश के नए बौद्ध समुदाय की उत्पत्ति 1956 में बाबासाहेब अंबेडकर के नेतृत्व में हुई, जिन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया था। यह उनका जातिगत भेदभाव के खिलाफ विरोध का प्रतीक था।

दूसरी ओर, ईसाई धर्म का भारत में एक जटिल इतिहास रहा है। केरल के बाहर, जहां ईसाइयों की एक प्राचीन धार्मिक विरासत है, ईसाई धर्म को औपनिवेशिक शासन से जोड़ा जाता है। यह धारणा कि ईसाई केवल विदेशी शासन के साथ जुड़े थे, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को कमतर करती है। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे क्षेत्रों में ईसाई स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी भुला दिया गया है।

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। संविधान में धर्म मानने, व्यवहार करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में 12 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे ईसाई समुदाय को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे संविधान और कानूनी ढांचे के तहत अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करें। लेकिन, दुर्भाग्य से, कई बार चर्च ने खुद को सत्ता के सामने झुका दिया है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल के शासन में हो।

> ***धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक बदलाव***
>
> *स्वतंत्रता के 77 वर्षों बाद भी, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता एक चुनौतीपूर्ण विषय बना हुआ है। देश ने विभिन्न धर्मों के लिए सुरक्षा के प्रयास किए, लेकिन हाल के वर्षों में धार्मिक विभाजन और घृणा की राजनीति ने समाज में असंतोष और हिंसा को जन्म दिया है।*

आज के भारत में, हर धार्मिक समुदाय को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। ईसाई समुदाय ने हमेशा अन्य धार्मिक समुदायों के साथ मिलकर काम नहीं किया है, जिनमें से कुछ को गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक दल और सरकारें, अपनी रणनीति के तहत, इन विभाजनों को और गहरा कर रही हैं।

भारत की स्वतंत्रता के 77 वर्षों बाद भी, धर्म और राजनीति के बीच का यह जटिल संबंध देश की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यह आवश्यक है कि हम सभी धर्मों के लोगों के लिए एक सुरक्षित और समान समाज की दिशा में काम करें, जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता हो।

(लेखक : वरिष्ठ पत्रकार एवं मानवाधिकारों और विशेष रूप से अल्पसंख्यको की स्थिति पर मुखर है, वह मीडिया मैप के सम्पादकीय समाचार मंडल के सदस्य भी है।)

राजनीतिक परिदृश्य

गठबंधन की राजनीति में फंसी मोदी सरकार

एन सत्यामूर्ति

लोकसभा चुनावों के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा अपने दृष्टिकोण में बदलाव करेगी। यह विशेष रूप से इसलिए माना जा रहा था क्योंकि मोदी पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। धारणा यह थी कि भाजपा अब अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर सामूहिक भलाई के लिए कार्य करेगी। लेकिन चुनाव के बाद की घटनाओं ने इन अटकलों को गलत साबित कर दिया।

भाजपा ने अपनी शासन शैली में बदलाव लाने का फैसला नहीं किया है। पार्टी पिछले एक दशक में जो रणनीति अपनाती आ रही थी, उसी के चक्र में फंसी हुई नजर आती है। मोदी सरकार, जिसने बिना किसी चुनौती के सत्ता का आनंद लिया, अब गठबंधन की राजनीति से उपजी जटिल चुनौतियों से निपटने में अनिश्चित दिख रही है। वे पुरानी रणनीतियों पर ही चलते हुए यह उम्मीद कर रहे हैं कि उनके विरोधी पहले अपनी प्रतिक्रिया देंगे, जिससे भाजपा अपनी चालाकी से जवाब दे सके।

इस रणनीति का असर न केवल प्रशासन पर पड़ा है, बल्कि भाजपा और विपक्षी दलों के बीच संबंधों पर भी पड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार भाजपा के निशाने पर हैं, और प्रधानमंत्री खुद इस हमले का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बावजूद, भाजपा अब भी उन्हें "राष्ट्र-विरोधी" करार देती रहती है। ऐसा लगता है कि भाजपा को लगता है कि यह बयानबाजी अब भी जनता पर असर डाल सकती है।

अब सवाल उठता है कि क्या यह नकारात्मक प्रचार भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा। हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव इसके जवाब दे सकते हैं। जम्मू-कश्मीर भाजपा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगर पार्टी जम्मू क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो इसे कांग्रेस और विपक्ष पर एक बड़ी जीत के रूप में पेश किया जाएगा। लेकिन अगर नतीजे उम्मीदों के विपरीत रहे, तो भाजपा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के रूप में दिखा सकती है और असफलताओं का ठीकरा बाहरी ताकतों पर फोड़ सकती है।

जम्मू-कश्मीर में भाजपा की रणनीति में राम माधव की मौजूदगी पिछले विवादास्पद पीडीपी गठबंधन की याद दिलाती है। सत्ता पाने के लिए भाजपा ने अपने मतभेदों के बावजूद पीडीपी के साथ हाथ मिलाया था। जब पीडीपी ने भाजपा से ज्यादा लाभ उठाना शुरू किया, तो भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया, जिससे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

> ***भाजपा का अनिश्चित भविष्य:***
> *लोकसभा चुनावों के बाद, भाजपा ने अपने दृष्टिकोण में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, जबकि गठबंधन की राजनीति की जटिलताओं से निपटने में पार्टी असहज महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अभी भी अपनी पुरानी रणनीतियों पर निर्भर करती दिखाई दे रही है।*

मोदी सरकार ने हाल के महीनों में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जो उनके सहयोगी दलों की वफादारी की परीक्षा ले रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल और सरकारी पदों पर पार्श्व प्रवेश के प्रस्ताव जैसे विवादास्पद मुद्दों पर सहयोगी दलों की प्रतिक्रिया को देखते हुए भाजपा की रणनीति चालाकी भरी नजर आती है। अगर सहयोगी समर्थन करते हैं, तो भाजपा जीतती है, और अगर वे विरोध करते हैं, तो भाजपा इसे मुद्दों को हल करने की अपनी कोशिश बताकर उनके विरोध को असहयोग के रूप में चित्रित करती है।

जाति जनगणना का मुद्दा, विशेष रूप से बिहार में, भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके पक्ष में लगातार आवाज उठा रहे हैं। यह एक संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि भाजपा एससी-एसटी समुदायों को अलग-थलग नहीं करना चाहती, लेकिन अपने सहयोगियों की मांगों को राजनीतिक एजेंडे के साथ संतुलित करना उसके लिए कठिन हो रहा है।

भाजपा की यह स्थिति 1998 के "चेन्नई घोषणापत्र" की याद दिलाती है, जब पार्टी ने विवादास्पद हिंदुत्व मुद्दों को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया था, जब तक कि उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। यह रणनीति उस समय कारगर साबित हुई, लेकिन अंततः आंतरिक मतभेदों के कारण सरकार गिर गई।

आज भाजपा खुद को फिर से ऐसे ही एक मोड़ पर पाती है। पार्टी भारतीय राजनीति में प्रमुख शक्ति बनी हुई है, लेकिन उसे गठबंधन की राजनीति के महत्व को समझकर संभलकर चलना होगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता सरकार को गिराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर भाजपा के लिए गठबंधन की राजनीति को नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है।

निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि भाजपा की पुरानी रणनीतियां भले ही कारगर रही हों, पर अब राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। पार्टी को नकारात्मक प्रचार और विभाजनकारी बयानबाजी पर निर्भर रहने के बजाय नए तरीकों को अपनाना होगा। विधानसभा चुनाव और गठबंधन की राजनीति की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच, भाजपा की अनुकूलन क्षमता ही उसकी भविष्य की सफलता का निर्धारण करेगी।

(लेखक चेन्नई स्थित नीति विश्लेषक और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं)

बैंकों में जमा राशि में गिरावट: अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट के संकेत

प्रो शिवाजी सरकार

भारत का बैंकिंग क्षेत्र गंभीर जमा संकट का सामना कर रहा है, जो विनिर्माण, ऑटोमोबाइल उद्योग और फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले गहरे मुद्दों को दर्शाता है। यह संकट व्यापक मंदी को उजागर करता है जो पूरे देश में व्यक्तिगत आजीविका और उद्योगों दोनों को प्रभावित कर रहा है।

इस मंदी के सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक FMCG क्षेत्र में बिक्री वृद्धि में गिरावट है। नीलसनआईक्यू के अनुसार, जून तिमाही के पहले दो महीनों के दौरान बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में मूल्य और मात्रा दोनों में गिरावट देखी गई। यह गिरावट इस बात का प्रारंभिक संकेत है कि मांग में अभी सुधार होना बाकी है। इसके अतिरिक्त, चावल, रत्न, आभूषण और समुद्री उत्पादों सहित 30 प्रमुख वस्तुओं का निर्यात या तो स्थिर हो गया है या घट गया है, कुल निर्यात 31.83 बिलियन डॉलर पर है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने भारत की यात्रा के दौरान बताया कि देश में 7 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, लेकिन यह पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर रहा है, जो बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। बिहार में 5.9 प्रतिशत से लेकर असम में 5.1 प्रतिशत तक राज्यों में अलग-अलग मुद्रास्फीति दर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लिए एक चुनौती है। बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति ने लोगों के पास अन्य आवश्यकताओं के लिए डिस्पोजेबल आय की मात्रा को कम कर दिया है, जिससे एक लहर प्रभाव पैदा होता है जो खर्च को बाधित करता है और व्यापक अर्थव्यवस्था को धीमा कर देता है।

आरबीआई की जुलाई की आर्थिक समीक्षा से पता चलता है कि आम आर्थिक स्थिति में लोगों का भरोसा कम हुआ है, साथ ही मौजूदा रोजगार और आय के बारे में भावनाएं भी खराब हुई हैं। यह जुलाई 2024 के आरबीआई के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के निष्कर्षों से मेल खाता है, जो आर्थिक स्थितियों के बारे में परिवारों के बीच आशावाद में गिरावट को दर्शाता है। इन चिंताओं में घरेलू बचत में तेज गिरावट भी शामिल है, जो भारत की विकास कहानी का एक महत्वपूर्ण चालक रहा है। 2022-23 में, घरेलू बचत घटकर सिर्फ़ 14.16 प्रतिशत रह गई, जो पिछले तीन वर्षों में एक महत्वपूर्ण गिरावट है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर भी संघर्ष कर रहा है। कई आम नागरिकों को नई कारें खरीदने में मुश्किल हो रही है क्योंकि वे अपनी पुरानी गाड़ियों की कीमत नहीं चुका पा रहे हैं। इस बीच, मुद्रास्फीति और लगातार कीमतों में बढ़ोतरी ने नई कारों को बहुत महंगा बना दिया है।

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 14 जून, 2024 तक बैंकों में जमा राशि में इस साल अब तक 3.5 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है, जो पिछले साल की तुलना में 1.6 प्रतिशत की गिरावट है। 26 जुलाई तक जमा राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि गैर-खाद्य ऋण में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो दर्शाता है कि बैंकिंग क्षेत्र और व्यापक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए जमा वृद्धि एक चुनौती बनी हुई है। जमा राशि में गिरावट सीधे तौर पर आय में कमी, क्रय शक्ति में कमी और समग्र मांग में मंदी से जुड़ी है। ऑटोमोबाइल उद्योग भी बिना बिके वाहनों के विशाल भंडार से जूझ रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अनुसार, देश भर में डीलरशिप पर लगभग 73,000 करोड़ रुपये मूल्य के 7 लाख से अधिक यात्री वाहन बिना बिके पड़े हैं। इस वजह से मारुति सुजुकी जैसी ऑटोमेकर कंपनियों ने उत्पादन कम करने की योजना की घोषणा की है। यहां तक कि लग्जरी कार निर्माता होंडा ने भी अपनी क्षमता में कटौती की है और इसके कुछ डीलरों ने अपनी दुकानें प्रतिस्पर्धियों को बेच दी हैं। ऑटो लोन की वृद्धि में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे उद्योग पर और अधिक असर पड़ा है।

उद्योग में पहले से ही संकट के संकेत दिख रहे हैं, जैसा कि क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में दर्शाया गया है, जो अगस्त में तीन महीने के निचले स्तर 60.5 पर आ गया, जो जुलाई में 60.7 था। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में घरेलू बचत पिछले तीन वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपये घटी है, जो 2022-23 में 14.16 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। लगभग आधे परिवारों ने भोजन, शिक्षा, किराया और परिवहन जैसी बुनियादी ज़रूरतों की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए आय और बचत में गिरावट की रिपोर्ट की है। लोकल सर्किल्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार, कई परिवार अब अपनी बचत में से पैसे निकाल रहे हैं या सिर्फ़ अपना खर्च चलाने के लिए ऋण ले रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों में जमा राशि में गिरावट पर चिंता व्यक्त की है और बैंकों से अपने कामकाज में सुधार करने का आग्रह किया है। उनकी टिप्पणी से संकेत मिलता है कि देश के वित्तीय ढांचे में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। जिन नीतियों के कारण यह स्थिति पैदा हुई है उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। भारत को उन नीतियों से दूर रहना चाहिए जो जनता की कीमत पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अत्यधिक टोल को प्राथमिकता देती हैं।

जैसे-जैसे देश आगे बढ़ रहा है, सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए नीति में बड़े बदलाव आवश्यक हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और घरेलू बचत को बढ़ावा देना भारत के लिए एक उज्जवल आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम हैं।

लेखक : वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया गुरु हैं।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में उथल-पुथल का व्यापार पर गंभीर प्रभाव

प्रो शिवाजी सरकार

बांग्लादेश में चल रही अशांति का भारत भर के व्यवसायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कई क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। प्याज निर्यातकों से लेकर बड़ी कंपनियों तक, कई को भारी नुकसान हो रहा है, जिसमें शेयर बाजार भी शामिल है। हालाँकि बांग्लादेश भारत के कुल व्यापारिक व्यापार का केवल 2.5 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन इसका प्रभाव विभिन्न उद्योगों पर महसूस किया जाता है।

उदाहरण के लिए, दिल्ली और अन्य क्षेत्रों के ऑटो-पार्ट व्यापारी पश्चिमी भारत से पूर्वोत्तर में माल ले जाने के लिए ढाका पर निर्भर हैं। कोलकाता, लुधियाना, जयपुर और दिल्ली के छोटे व्यवसाय भी संकट का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण वे संकट के जवाब में एकजुट होने के लिए मजबूर हैं।

बांग्लादेश में अरबों डॉलर का निवेश करने वाले भारतीय समूह अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जबकि कई बांग्लादेशी फर्म भी इसी तरह प्रभावित हैं। यह उथल-पुथल सीमा पार काम करने वाले हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। दोनों देशों के छात्र भी इस स्थिति में फंसे हुए हैं, जो भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे, परस्पर जुड़े संबंधों को उजागर करता है जो केवल व्यापार और निवेश से परे हैं।

शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप भारत के लिए उल्लेखनीय व्यापार अधिशेष हुआ। उनके जाने से संभावित रूप से ये लाभ बाधित हो सकते हैं, जिससे माल और लोगों का प्रवाह प्रभावित हो सकता है और प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में देरी हो सकती है। भारतीय कपास किसानों को 1.2 बिलियन डॉलर का निर्यात खोना पड़ सकता है। कुल मिलाकर, 12.9 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दांव पर लगा है, हालांकि यह 2024 में घटकर 11 बिलियन डॉलर रह गया है और साथ ही बांग्लादेश को 8 बिलियन डॉलर का भारतीय ऋण भी है।

पिछले दो सालों में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। इसका विदेशी मुद्रा भंडार दो साल पहले के 48 बिलियन डॉलर से घटकर 15.82 बिलियन डॉलर रह गया है। 17 करोड़ में से 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से अर्थव्यवस्था में तेज़ी से मंदी आई है, जिससे ईंधन और खाद्य आयात की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसके कारण बांग्लादेश को पिछले साल 4.7 बिलियन डॉलर के बेलआउट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का रुख करना पड़ा।

अंतरिम सरकार की संरचना और नई व्यवस्था पर बेगम जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का प्रभाव भारत के बेहतर प्रदर्शन में बाधा बन सकता है। शेख हसीना द्वारा कुछ व्यापारिक घरानों का पक्ष लिए जाने के कारण भारत विरोधी भावनाएँ प्रबल हैं। अंतरिम प्रशासन के सामने शांति बहाल करने और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय, अवामी लीग (एएल) के नेताओं और समर्थकों को निशाना बनाए जाने वाले अतिउत्साही माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का कठिन कार्य है। यहाँ तक कि शेख मुजीबुर रहमान पर एक जीवनी फिल्म बनाने वाले एक फिल्म निर्माता और उनके बेटे को भी पीट-पीटकर मार डाला गया। हिंदू अल्पसंख्यकों, एएल नेताओं और कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्याओं की संख्या कई हज़ार को पार कर गई है। असंख्य महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ और अपहरण किया गया है।

बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं। अभिजात वर्ग के लोग बैठकें कर रहे हैं और अब अल्पसंख्यक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में 4 से 5 जिलों की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध एकता परिषद के अनुसार, कुछ

क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों द्वारा लुटेरों का विरोध करने के बावजूद, आगजनी और लूट व्यापक है। एएल को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, यह सामान्यीकरण के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालाँकि, जमात-ए-इस्लाम एक शक्तिशाली संगठन है। यह बैंकों, व्यवसायों, व्यापार, शैक्षणिक संस्थानों को नियंत्रित करता है और नई व्यवस्था में नीतियों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त प्रभाव रखता है।

भारत नए नेताओं के साथ संबंध बनाने में सावधानी बरत रहा है। बेगम जिया एक महत्वपूर्ण कारक होंगी।

भारत के प्रमुख निर्यातों में सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, चीनी, कन्फेक्शनरी, परिष्कृत पेट्रोलियम तेल, रसायन, कपास, लोहा और इस्पात तथा वाहन शामिल हैं, जबकि इसके मुख्य आयातों में मछली, प्लास्टिक, चमड़ा और परिधान शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और बांग्लादेश के बीच कुल व्यापार 1,35,285 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिसमें भारत के पास पर्याप्त व्यापार अधिशेष है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, बांग्लादेश में शांति और स्थिरता का समर्थन करने में भारत की रणनीतिक रुचि है और परिधान उद्योग को संरक्षित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, यह पश्चिम में भारतीय परिधान निर्यात को बढ़ावा दे सकता है जब तक कि ढाका घरेलू मामलों को ठीक नहीं कर लेता।

वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि इस अवधि के दौरान भारत ने बांग्लादेश को 91,614 करोड़ रुपये का सामान निर्यात किया, जबकि 15,268 करोड़ रुपये का सामान आयात किया। इसके परिणामस्वरूप भारत के पक्ष में 76,346 करोड़ रुपये का व्यापार अधिशेष हुआ। यह डेटा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार के रूप में बांग्लादेश की भूमिका को रेखांकित करता है, और किसी भी व्यवधान का दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा।

उल्लेखनीय रूप से, भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाएं महत्वपूर्ण रही हैं। 2016 से, भारत ने बांग्लादेश में सड़क, रेल, शिपिंग और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 8 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है। प्रमुख

परियोजनाओं में अखौरा-अगरतला रेल लिंक और खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन शामिल हैं, जिनका उद्घाटन नवंबर 2023 में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। इन परियोजनाओं में भारत का बड़ा निवेश फंसा हुआ है।

इन सम्पर्कों में व्यवधान से भारत की पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंच बाधित हो सकती है तथा चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के लिए मौजूदा बस मार्ग और समझौते खतरे में पड़ सकते हैं।

टाटा समूह, वीआईपी इंडस्ट्रीज, मैरिको, अदानी पावर, इमामी, हीरो मोटरकॉर्प, टीवीएस मोटर्स समेत कई भारतीय कंपनियों के बांग्लादेश के साथ मजबूत संबंध हैं। मैरिको को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ा है। मैरिको एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में व्यापक रूप से निर्यात करती है, लेकिन बांग्लादेश विशेष रूप से एक बड़ा बाजार है, जो वित्त वर्ष 2022 में कंपनी के अंतरराष्ट्रीय कारोबार का 51 प्रतिशत हिस्सा है, और कथित तौर पर कुल बिक्री का 11 प्रतिशत से 12 प्रतिशत प्राप्त करता है। शेयर की कीमत इस चिंता के कारण गिर गई कि बांग्लादेश में बिक्री में कमी से मैरिको की आय कम हो जाएगी।

इसका असर प्याज किसानों पर भी पड़ रहा है। भारत अपने प्याज उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत बांग्लादेश को निर्यात करता है।

बांग्लादेश में ऑटो मोटर स्पेयर पार्ट्स की बहुत मांग है क्योंकि दोनों देशों में एक ही ब्रांड के ज़्यादातर दोपहिया और चार पहिया वाहन बेचे जाते हैं। चैंबर ऑफ़ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का कहना है कि दिल्ली से हर महीने 1000 करोड़ रुपये के सामान निर्यात किए जाते हैं। श्रीलंका में उथल-पुथल के दौरान इस सेक्टर को नुकसान उठाना पड़ा था। नए ऑर्डर मिलना संभव नहीं है लेकिन पुरानी खेपें भुगतान की परेशानी में फंसी हुई हैं।

पंजाब में कई छोटे-छोटे व्यवसाय हैं, जो पूर्वोत्तर में अपना माल भेजने के लिए ढाका मार्ग का उपयोग करते हैं। उन्हें दोहरा लाभ मिलता है। भारत से बांग्लादेश को भेजी जाने वाली खेप से निर्यात प्रोत्साहन मिलता है और इसी तरह उनकी कंपनी द्वारा पूर्वोत्तर में पुनः निर्यात करने से उन्हें ढाका से एक और प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा इससे पारगमन और परिवहन समय और खर्च की बचत होती है। इसी तरह के संबंध विभिन्न कोनों से हैं।

हाल ही में हुए नरसंहार में देश भर में रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवे जैसी प्रमुख सरकारी संपत्तियां नष्ट हो गई हैं। पुनर्निर्माण में समय लगेगा। सरकारी अधिकारी दफ्तर जाने से कतराते हैं और निजी उद्योगों को फिर से काम शुरू करने में लंबा समय लग सकता है। यह भारत के लिए नहीं बल्कि उपमहाद्वीप के लिए नुकसान है।

आज भी दलितों के लिए अच्छा जीवन एक सपना

प्रशांत गौतम

भारत की आज़ादी के 77 साल बाद भी, यह सवाल एक गूंजती हुई हकीकत है कि क्या दलित आज भी आज़ाद हैं? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। लेकिन आज भी दलित समुदाय के लोग समानता और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

स्वतंत्रता संग्राम के समय, हमारे देश के नेताओं ने एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखा था, जहाँ हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक प्रयास किए। संविधान में दलितों को आरक्षण और विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके। लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी, क्या ये प्रावधान वास्तविकता में बदल पाए हैं?

भारत के विभिन्न हिस्सों में आज भी दलितों के साथ भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं आम हैं। कई गांवों में दलितों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती, उनके बच्चों को स्कूलों में अलग बैठाया जाता है, और उनके घरों को अक्सर मुख्य गांव से अलग स्थान पर बनाया जाता है। यह भेदभाव केवल गांवों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहरों में भी दलितों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

इसी तरह, द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी उनके आदिवासी समुदाय से जुड़े होने के कारण कुछ मंदिरों में प्रवेश न दिए जाने की घटनाओं की खबरें आई थीं।

रामनाथ कोविंद जब 2017 में राष्ट्रपति बने थे, तब उनके बारे में खबरें आई थीं कि उन्हें गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था।

एक व्यक्ति एक वोट देकर राजनितिक बराबरी तो दे दी, मगर एक देश में सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी दूर नहीं हुई तो राजनितिक बराबरी के कोई मायने नहीं निकलेंगे। क्या लगता है आज भी सामाजिक और गैरबराबरी दूर हुई ? आज भी घोड़ी चढ़ने पर किसी को मारा जाता है, मुछ रखने पर मारा जाता है।

इस स्वतंत्र दिवस पर याद करे उस बच्चे इंद्रा मेघवाल को जिसको पानी पीने के मटके को छूने पर पिट पिट कर हत्या कर दी गयी.याद करे हाथरस की बहन को जाति देख कर जिसको अमानवीय प्रतारणा दी गयी।

याद करे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के खारडा गांव की 16 वर्षीय कल्पना जाधव की कहानी इसका एक दुखद उदाहरण है। कल्पना ने अपने गांव के स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छे अंक हासिल किए। लेकिन स्कूल के शिक्षकों ने उसे सम्मान नहीं दिया, और उसके सहपाठियों ने उसके साथ जातिगत भेदभाव किया। एक दिन, जब कल्पना ने अपने सहपाठियों के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, तो उसे बेरहमी से पीटा गया और अंततः उसने आत्महत्या कर ली। ऐसी कई कहानियां हैं जो यह दर्शाती हैं कि हमारे समाज में दलितों के लिए स्वतंत्रता केवल कागजों तक सीमित है।

> ***दलितों की स्वतंत्रता का अधूरा सपना***
> *आज़ादी के 77 साल बाद भी दलितों के लिए स्वतंत्रता सिर्फ कागजों पर सीमित है। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दलितों को समान अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण और विशेष सुविधाएं दीं, लेकिन जातिगत भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं अब भी जारी हैं। गांवों से लेकर शहरों तक दलित समुदाय को समानता के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हमें इस स्वतंत्रता दिवस पर यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या सच में सभी भारतीय समान हैं?*

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते है मैं (o b c) माँ का बेटा हूँ। और तब (o b c) जाग गया और बोला की जातिजनगर्णा करनी है तो मोदी बोलते है मेरी नज़रो में एक ही जाति होती है गरीब। जब वोट लेना हुआ तो (o b c) बन गए और तब (o b c) ने अधिरक माँगा तो बोले हम गरीब ही है गरीब को ही वोट देते है। ऐसे बनानेगा बराबर समाज ?

हालांकि सरकार ने दलितों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन इनका प्रभाव ज़मीन पर दिखाई नहीं देता। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, और दलितों के लिए विशेष आरक्षण योजनाएं, ये सभी पहलें अच्छी हैं, लेकिन इनके क्रियान्वयन में कई खामियां हैं।

दलित नेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। चाहे वह मायावती हों या जिग्नेश मेवाणी, इन नेताओं ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। लेकिन उनकी कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकतीं जब तक समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव की जड़ें खत्म नहीं होतीं।

दलित समुदाय की वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम आर्थिक और सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता दें। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में समानता लाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमें समाज में जागरूकता फैलाने और भेदभाव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हम सभी मिलकर जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है। हमें यह समझना होगा कि स्वतंत्रता केवल कुछ लोगों का अधिकार नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय का अधिकार है।

भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन दलितों के लिए वास्तविक स्वतंत्रता का सपना अभी भी अधूरा है। हमें यह समझना होगा कि केवल कानून और योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। हमें अपने मानसिकता और सामाजिक ढांचे में बदलाव लाना होगा। तभी हम एक सच्चे स्वतंत्र और समान समाज की कल्पना कर सकते हैं।

देश को स्वतंत्र हुए 77 साल हो गए हैं, अब समय आ गया है कि हम दलितों की स्वतंत्रता के बारे में भी गंभीरता से सोचें और उन्हें वह सम्मान और समानता दिलाएं जिसके वे हकदार हैं।

आइए, हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहाँ हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, समानता और सम्मान के साथ जी सके।*

लेखक : मीडिया मैप के मुख्य सह-संपादक है।

क्या कनाडा में भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बनेगा

प्रभजोत सिंह

कनाडा के लोग ऐसी सरकार के हकदार हैं, जो केवल न्यू डेमोक्रेट्स ही दे सकते हैं - जो काम पूरा करे, जो अपने वादे पूरे करे। इसीलिए आज (1 अक्टूबर, 2017) मैं आधिकारिक तौर पर कनाडा का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना अभियान शुरू कर रहा हूं," यह बयान जगमीत सिंह ने कनाडा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी (वर्तमान में सत्तारूढ़ लिबरल, मुख्य विपक्षी कंजर्वेटिव और ब्लॉक क्यूबेकॉइस के बाद चौथे स्थान पर) के नेतृत्व की दौड़ में कुल पात्र मतों में से 53.8 प्रतिशत मतों के साथ विजयी होने के बाद दिया।

सात साल बाद, वे फिर से चर्चा में हैं। इस बार न केवल सत्तारूढ़ (हालांकि अल्पमत) के साथ लगभग 30 महीने पुराने समझौते को तोड़ने के लिए, बल्कि खुद को फिर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए भी, यह कहते हुए कि उन्हें कंजर्वेटिवों को बाहर रखना है।

अक्टूबर 2017 में जब उन्होंने यह बयान दिया, तो इसने सत्तारूढ़ लिबरल कॉकस के सदस्यों को चौंका दिया होगा और कनाडा की राजनीति के क्षितिज पर एक नए सितारे के उभरने का एहसास कराया होगा। शीर्ष पद के लिए अपने अभियान में, जगमीत सिंह - सौम्य, करिश्माई और ऊर्जावान - ने न केवल 47,000 नए सदस्यों को नामांकित किया, जिसमें ओंटारियो में 30,000 शामिल थे - जो कभी लिबरल्स का गढ़ था - बल्कि तीन और अनुभवी विरोधियों को भी धूल चटाकर ऐतिहासिक पहले बैलट की जीत दर्ज की, जिसे ओंटारियो के सांसद चार्ली एंगस के साथ सीधा या करीबी मुकाबला माना जाता था, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के स्थायी सदस्य हैं।

जगमीत सिंह, जो अक्सर अपने अभियान के दौरान अपने परिवार के संघर्ष की कहानी सुनाते थे, चाहते थे कि कनाडा के लोग डर की राजनीति के बजाय साहस की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हों। वामपंथी होने के कारण, मजदूरों का मुद्दा उनके दिल के बहुत करीब है।

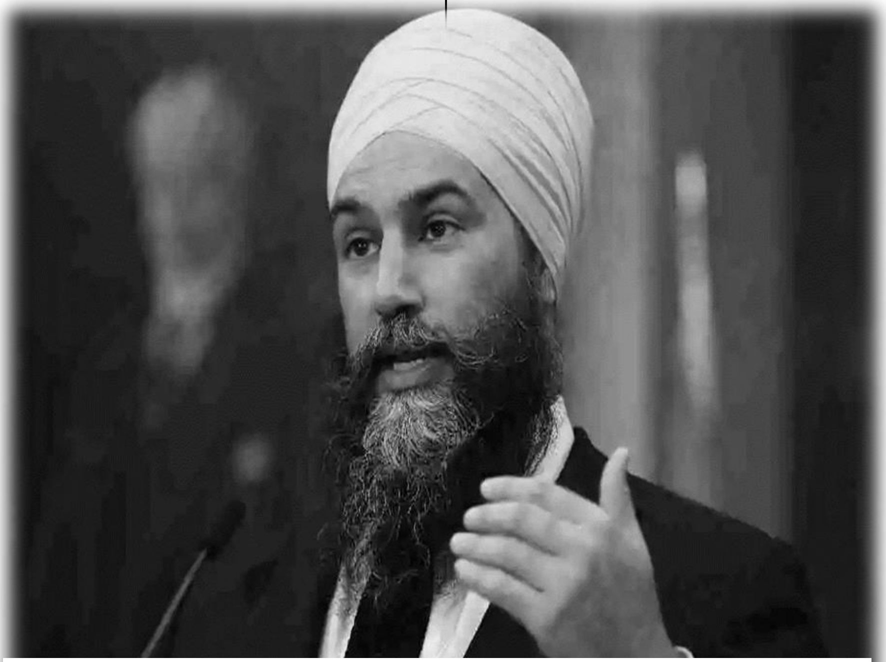

जगमीत सिंह

संघीय राजनीति में कई लोगों ने उन्हें "गेम चेंजर" माना। राजनीति में उनका उदय धीरे-धीरे और अभूतपूर्व रहा। स्कारबोरो में पंजाबी माता-पिता के घर जन्मे जगमीत सिंह अंग्रेजी, पंजाबी और फ्रेंच बोलते हैं। उन्होंने अपने बचपन के कुछ साल भारत के पंजाब में अपने दादा-दादी के साथ बिताए, क्योंकि उनके पिता, एक योग्य मनोचिकित्सक, को अपने अभ्यास के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनके पिता को अजीबोगरीब काम करने पड़े, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी की नौकरी भी शामिल थी। एक समय जब उनके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, तो जगमीत सिंह को अपने भाई गुररतन सिंह की शिक्षा सहित परिवार की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ी, जो बाद में ओंटारियो प्रांतीय संसद में बैठे।

उन्होंने 2018 में गुरकिरन कौर सिद्धू से शादी की और अब वे दो बच्चों के गौरवान्वित पिता हैं।

जगमीत की धन जुटाने और संगठन कौशल की परीक्षा नेतृत्व की दौड़ में हुई, जहाँ पहले ही बैलट में उन्होंने न केवल अपने तीनों प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि उन्हें पछाड़ भी दिया। वह एनडीपी में एक संपूर्ण पैकेज के रूप में आए।

पार्टी के भीतर और बाहर दोनों तरफ से हमलों का सामना करते हुए जगमीत सिंह

के पास 2019 में होने वाले अगले संघीय चुनावों से पहले पूरे कनाडा में पार्टी की उपस्थिति बनाने के लिए केवल दो वर्ष का समय था, जहां 338 सदस्यीय सदन में तब पार्टी के 44 प्रतिनिधि थे।

पार्टी के 1,24,000 सदस्यों द्वारा नए नेता के चुनाव के लिए मतदान करने से ठीक पहले, निवर्तमान प्रमुख थॉमस मुलकेयर ने एक ऐसा बयान दिया जिसे कई लोगों ने जगमीत सिंह के लिए हानिकारक माना। थॉमस मुलकेयर ने टिप्पणी की "पार्टी के अगले नेता के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी लिबरल ब्रिगेड का विरोध करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट होना महत्वपूर्ण है।

जगमीत सिंह नेतृत्व की दौड़ में एकमात्र गैर-सांसद थे, क्योंकि उनके तीनों प्रतिद्वंद्वी - चार्ली एंगस, निकी एश्टन और गाय कैरन - ओंटारियो, मैनिटोबा और क्यूबेक का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा सांसद थे।

जगमीत सिंह का करिश्माई नेतृत्व: *2017 में जगमीत सिंह ने अपनी करिश्माई और ऊर्जावान नेतृत्व शैली से न केवल एनडीपी का नेतृत्व किया, बल्कि अपने अभियान में 47,000 से अधिक नए सदस्यों को भी जोड़ा, जिसमें ओंटारियो में 30,000 सदस्य शामिल थे। यह उनके नेतृत्व कौशल का प्रमाण है, जिसने कनाडा की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा।*

हालांकि यह दुर्लभ था लेकिन असामान्य नहीं था कि प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी के नेता ट्रेजरी बेंच का विरोध करने के लिए संसद में न बैठें, जगमीत सिंह को नेतृत्व की दौड़ में शामिल होने का फैसला करने से पहले एक कठिन निर्णय लेना था। ओंटारियो एनडीपी विधायक दल के उप नेता के रूप में, वह 2018 के विधानसभा चुनावों में प्रीमियरशिप के लिए एक मजबूत उम्मीदवार होते।

जगमीत सिंह को संसद में जाने के लिए उपचुनाव लड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। बल्कि वे पूरे देश में पार्टी का आधार मजबूत करना चाहते थे, खासकर ओंटारियो और क्यूबेक में, जहां से उनके पूर्ववर्ती जैक लिटन 2003 में पार्टी छोड़कर चले गए थे।

उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने की कोई जल्दी नहीं थी। 8 अगस्त, 2018 को जगमीत सिंह ने घोषणा की कि वह कैनेडी स्टीवर्ट द्वारा खाली की गई सीट के खिलाफ बर्नबी साउथ से उपचुनाव में भाग लेंगे। कैनेडी स्टीवर्ट ने बाद में वैंकूवर के मेयर पद के लिए सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। जगमीत सिंह बर्नबी चले गए। 25 फरवरी, 2019 को उन्हें 38.9 प्रतिशत वोट के साथ हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित घोषित किया गया।

आठ महीने बाद जब अगला संघीय चुनाव होने वाला था, तो 21 अक्टूबर 2019 को सिंह बर्नबाई साउथ राइडिंग से फिर से चुने गए।

जगमीत के लिए यह कोई स्वप्निल शुरुआत नहीं थी क्योंकि एनडीपी पिछले हाउस ऑफ कॉमन्स में 44 सीटों के मुकाबले केवल 24 सीटें ही जीत पाई। 2004 के बाद से एनडीपी के लिए यह सबसे कम सीटें थीं क्योंकि यह कनाडा की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी से खिसककर चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ब्लॉक क्यूबेकॉइस ने इसे पीछे छोड़ दिया क्योंकि एनडीपी ने क्यूबेक में एक सीट को छोड़कर सभी सीटें खो दीं।

मौजूदा ट्रूडो लिबरल सरकार अपना बहुमत बरकरार रखने में विफल रही। संघीय राजनीति में सत्ता के संतुलन को साझा करने में एनडीपी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद, उन्हें 44 वें हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए फिर से चुना गया। एनडीपी 25 सीटों के साथ चौथी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनी रही।

साहस की राजनीति के समर्थक:
जगमीत सिंह अपने परिवार के संघर्ष की कहानी सुनाते हुए हमेशा साहस की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। वह डर की राजनीति को खत्म करने और कनाडाई लोगों को एकजुट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मजदूरों के हितों की रक्षा करना उनके दिल के बेहद करीब है, जो उनकी वामपंथी विचारधारा को दर्शाता है।

22 मार्च, 2022 को जगमीत सिंह के नेतृत्व में एनडीपी ने अल्पमत लिबरल सरकार के साथ विश्वास और आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

समझौते के अनुसार सरकार को 2023 के अंत तक फार्मा केयर लागू करना होगा। इसके अलावा, कम आय वाले कनाडाई लोगों के लिए डेंटल केयर प्रोग्राम सरकार की प्राथमिकता होगी जिसे 2025 तक लागू किया जाएगा।
4 सितंबर, 2024 को, सिंह ने स्वास्थ्य सेवा सुधारों और सामर्थ्य उपायों पर उदारवादियों के प्रदर्शन से असंतोष का हवाला देते हुए 2022 के विश्वास और आपूर्ति समझौते को रद्द कर दिया।

प्रभजोत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, खेल कूद पत्रकार्ता में उनकी विशेष रूचि है और उन्होंने सात ओलंपिक कवर किए हैं। खेल-कूद के साथ ही वे व्यापार, वित्त, स्वास्थ्य, विमानन और सिख-पंजाब राजनीति के भी विशेषज्ञ माने जाते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के साथ बदलती नयी दुनिया कैसी होगी

प्रशांत गौतम

क्या आपको भी लगता है कि तकनीकी विकास आपके करियर के लिए खतरा बन सकता है? क्या आपके मन में यह डर समा गया है कि आपकी नौकरी मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारण खतरे में है? यदि हाँ, तो यह समय है इस डर को और गंभीरता से समझने का। तकनीक का उभरता हुआ क्षेत्र तेजी से बदल रहा है और इसका असर सीधे तौर पर हमारी नौकरियों पर पड़ रहा है। आज हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ AI और रोबोटिक्स ने कई मानवीय कार्यों को संभाल लिया है, जिससे हमारी नौकरियाँ गंभीर खतरे में पड़ सकती हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, का मुख्य उद्देश्य मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता प्रदान करना है। इसका मतलब यह है कि जो कार्य पहले इंसानों द्वारा किए जाते थे, अब वे मशीनें भी कर सकती हैं। हालाँकि, AI के कई फायदे हैं, लेकिन इससे जुड़े खतरों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस लेख में, हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी नौकरियों को खत्म करने का कारण बन रही है और हमें इससे कैसे निपटना चाहिए।

AI और रोबोटिक्स आज के समय में विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। यह प्रगति न केवल तकनीक के क्षेत्र में है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। एक समय था जब मशीनों का उपयोग केवल सीमित कार्यों के लिए होता था, लेकिन आज AI मशीनें ऐसे कार्य करने में सक्षम हैं, जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी।

एक अध्ययन के अनुसार, 2030 तक दुनिया की 50% नौकरियाँ AI और रोबोट्स द्वारा की जाएंगी। इससे सीधा मतलब है कि उन नौकरियों का भविष्य अंधकारमय है, जिनमें क्रिएटिविटी, विश्लेषणात्मक क्षमता या इंसानी समझ की आवश्यकता नहीं होती। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप भी उस सूची में हैं?

तकनीक ने सबसे पहले उन नौकरियों को

निशाना बनाया है, जो दोहराव वाली हैं, यानी जिनमें रचनात्मकता या विशेष समझ की आवश्यकता नहीं होती। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, ड्राइवर, डिलीवरी बॉय जैसे पेशे अब सीधे AI और रोबोट्स के कब्जे में हैं।

- फैक्ट्री मजदूर: फैक्ट्री में काम करने वाले हजारों लोग अब बेरोजगारी के कगार पर हैं। स्वचालित मशीनें अब उन कार्यों को कर रही हैं, जो पहले इंसान किया करते थे। चीन और जापान में कई फैक्ट्रियों में मानव श्रम की आवश्यकता लगभग समाप्त हो चुकी है, और इस चलन से भारत भी अछूता नहीं रहेगा।

- ड्राइवर: सेल्फ-ड्राइविंग कारों का विकास तेजी से हो रहा है। टेस्ला जैसी कंपनियों ने ऐसे वाहन विकसित किए हैं, जो इंसानों की बजाय खुद से सड़कों पर दौड़ते हैं। इस तकनीक के चलते टैक्सी ड्राइवरों और ट्रक ड्राइवरों की नौकरियाँ खत्म होने की संभावना है। अमेरिका में यह तकनीक पहले से ही मौजूद है, और भारत में भी इसका असर देर-सवेर देखने को मिलेगा।

- डिलीवरी बॉय: अमेज़ॉन जैसी कंपनियाँ अब ड्रोन का उपयोग करके डिलीवरी करने लगी हैं। यह साफ संकेत है कि डिलीवरी से जुड़े हजारों नौकरियों का अंत हो सकता है। ड्रोन के जरिए यह काम तेज और सटीक तरीके से किया जा सकता है, अमेज़ॉन पहली अपनी करियर डेलिवरी ड्रोन के साथ कर चुका है। जिससे मानव श्रम की आवश्यकता कम हो जाएगी।

- अकाउंटेंट: अमेज़न गो ने हाल ही में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अमेज़न गो की मोबाइल ऐप के जरिए आप सीधे उनके स्टोर में प्रवेश कर सकते हैं। स्टोर में लगे हाई-टेक सेंसर्स के कारण आपको बस सामान उठाना है और बाहर निकलना है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आपका बिल आपके अमेज़न अकाउंट से अपने आप कट जाता है। न लाइन में लगने की जरूरत, न काउंटर पर पेमेंट करने की। यह सुविधा जितनी आसान है, उतनी ही डरावनी भी। इसका सीधा मतलब है कि अब अकाउंटेंट्स और कैशियर की नौकरियां खतरे में हैं।

- सिक्योरिटी गार्ड : इमेज रेकग्निशन सॉफ्टवेयर और पैटर्न्स पहले से ही विकसित हो चुके हैं। ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका तेजी से कम होती जा रही है। अब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट्स को तैयार किया जा सकता है, जिससे कंपनियां भारी मात्रा में पैसा बचा सकती हैं। इन रोबोट्स को न

तो मासिक सैलरी की जरूरत होती है और न ही इंसानों की तरह छुट्टियों की। बस थोड़ी बहुत मेंटेनेंस की जरूरत होती है, और वे लगातार काम करते रहते हैं। इसका मतलब साफ है—सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरियां भी अब खतरे में हैं।

- पत्रकारों और रिपोर्टरों : पत्रकारों और रिपोर्टरों की नौकरियों पर AI का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। AI आधारित टेक्नोलॉजी अब न्यूज़ रिपोर्टिंग, लेखन और कंटेंट जनरेशन जैसे कार्यों को बड़ी आसानी से संभाल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटेड तरीके से न्यूज़ आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और यहां तक कि लाइव कवरेज भी तैयार कर सकता है। इसका मतलब है कि भविष्य में पत्रकारों की जगह रोबोट्स और सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। AI न केवल तेजी से काम करता है, बल्कि उसमें गलती की संभावना भी कम होती है। इसका ताज़ा उदाहरण है भारत की पहली AI एंकर "सना," जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित है और न्यूज़ रिपोर्टिंग में मानव एंकर की भूमिका को चुनौती दे रही है। इस तरह की टेक्नोलॉजी से पत्रकारों के लिए नौकरी की संभावनाएं कम हो सकती हैं, और उनकी रचनात्मकता और विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। यह परिवर्तन पत्रकारिता की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है।

तकनीकी विकास: क्या आपकी नौकरी सुरक्षित है?

तकनीक के तेज़ी से बढ़ते कदम हमारी नौकरियों पर भारी पड़ सकते हैं। जानिए कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स हमारी करियर संभावनाओं को बदल रहे हैं।

तकनीकी क्रांति से भले ही कई नौकरियाँ खतरे में हैं, लेकिन कुछ पेशे अभी भी सुरक्षित हैं। वे नौकरियाँ, जिनमें इंसानी समझ, निर्णय लेने की क्षमता, और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है, भविष्य में भी बनी रहेंगी।

- डॉक्टर्स और नर्सेस: चिकित्सा क्षेत्र में AI तेजी से प्रवेश कर रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर और नर्स जैसे पेशे सुरक्षित रहेंगे। कारण यह है कि इंसानी भावना, सहानुभूति, और नैतिकता का स्थान मशीनें नहीं ले सकतीं। रोगियों की देखभाल और जटिल बीमारियों का निदान अभी भी इंसानों द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है।

- प्रोफेसर और शिक्षक: शिक्षा के क्षेत्र में भी AI का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन शिक्षक और प्रोफेसर अभी भी महत्वपूर्ण रहेंगे। विद्यार्थियों को दिशा-निर्देश देने, प्रेरित करने और उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को समझने में मशीनें इंसानों का स्थान नहीं ले सकतीं।

- वैज्ञानिक और शोधकर्ता: वैज्ञानिक और शोध कार्यों में इंसानी दिमाग की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। नई खोजों और तकनीकी आविष्कारों के लिए इंसानों की सोच, रचनात्मकता, और विश्लेषणात्मक क्षमता महत्वपूर्ण है।

यदि आप एक सरल और दोहराव वाली नौकरी कर रहे हैं, तो यह समय है कि आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। तकनीक के इस युग में सुरक्षित रहने के लिए यह आवश्यक है कि आप नए कौशल सीखें और खुद को इस प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करें।

- स्किल अपग्रेडेशन: यह समय आराम करने का नहीं है। आपको लगातार अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। जैसे-जैसे तकनीक उभर रही है, वैसे-वैसे आपको भी नए कौशल सीखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से AI, डेटा साइंस, और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में महारत हासिल करने से आप भविष्य में भी अपनी नौकरी को सुरक्षित रख सकते हैं।

- शिक्षा में बदलाव: शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव की जरूरत है। आज की शिक्षा प्रणाली 10-15 साल बाद प्रासंगिक नहीं रहेगी। इसीलिए हमें ऐसी शिक्षा पर जोर देना होगा, जो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स) विषयों में शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी।

- रचनात्मकता का विकास: वह नौकरियाँ सुरक्षित रहेंगी, जिनमें रचनात्मकता और इंसानी दिमाग की जरूरत होती है। इसलिए, हमें अपनी रचनात्मकता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए।

2030 तक 50% नौकरियाँ AI के हवाले?

क्या आपकी नौकरी उन 50% में शामिल है, जिन्हें भविष्य में AI और रोबोट्स संभालेंगे? जानें, कौन-से पेशे सबसे ज़्यादा खतरे में हैं।

तकनीकी क्रांति हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन इसके खतरों को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। आज जो प्रोजेक्ट्स 3 साल में पूरे होते हैं, भविष्य में वे 30 दिनों में पूरे हो सकते हैं। इसी तरह, रोबोट और AI सिस्टम तेज गति से कार्य करने में सक्षम हो रहे हैं, जो मानव श्रम की मांग को कम कर सकते हैं।

इस बदलते समय में टिके रहने के लिए हमें सतर्क रहना होगा। खुद को अपग्रेड करते रहना ही सफलता की कुंजी होगी। यह एक डरावना समय जरूर है, लेकिन यह नए अवसरों का भी समय है। जो लोग इस तकनीकी बदलाव के साथ खुद को ढाल लेंगे, वे नई ऊँचाइयों को छू सकेंगे। लेकिन जो लोग समय के साथ नहीं बदलेंगे, वे पीछे छूट जाएंगे।

तो, सवाल यह नहीं है कि आपकी नौकरी खतरे में है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? AI और रोबोटिक्स का यह दौर हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ाने के लिए है। बस जरूरत है कि हम समय के साथ खुद को तैयार करें और इस बदलाव को अपनाएं।

आने वाला भविष्य उज्ज्वल है, बशर्ते हम इसके लिए तैयार हों।

लेखक : मीडिया मैप के मुख्य सह-संपादक है।

मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार और सरकार की खामोशी

डॉ. सलमान अरशद

मोदी सरकार और आरएसएस हमेशा भारतीय संस्कृति और उसकी रक्षा की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। जिस देश में संस्कृति की बात की जाती है, वहां मासूम बच्चियों के साथ दिन-प्रतिदिन होने वाले बलात्कार की घटनाएं सरकार और समाज की नाकामी को दर्शाती हैं। यह कैसी संस्कृति की रक्षा की जा रही है, जब बच्चियों की चीखें सुनने वाला कोई नहीं है? सरकार और संगठन सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। मासूमों के साथ बढ़ते अत्याचारों पर चुप्पी साधने वाले ये नेता किस संस्कृति की बात कर रहे हैं?

देश में हर दिन महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित हैं, और इसके बावजूद मोदी सरकार और आरएसएस अपने तथाकथित संस्कृति रक्षा के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर यही भारतीय संस्कृति की रक्षा है, तो इसका मतलब सिर्फ खोखले दावे और असल समस्याओं से आंखें मूंद लेना है। बलात्कार की घटनाएं हमारे समाज और सरकार के विफल होने का स्पष्ट उदाहरण हैं। यह सरकार अगर सच में संस्कृति की रक्षा करना चाहती है, तो सबसे पहले उसे इन घिनौने अपराधों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे, वरना 'संस्कृति' शब्द केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा।

कोलकाता में हुई हालिया बलात्कार की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक मासूम लड़की के साथ जो बर्बरता हुई, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। उस मासूम की चीखें आज भी हमारे कानों में गूंजती हैं, जो अपनी अस्मिता और जीवन के लिए लड़ती रही। लेकिन उन दरिंदों ने उसकी आवाज को बेरहमी से दबा दिया। इस जघन्य कृत्य ने न केवल उसकी अस्मिता को रौंदा, बल्कि हमारी इंसानियत को भी तार-तार कर दिया है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारे समाज में ऐसे अमानवीय अपराध कब तक होते रहेंगे?

अलिगढ़ में पिछले साल एक दलित लड़की के साथ हुए दुष्कर्म की घटना ने समाज को हिला कर रख दिया। उस नासमझ लड़की को बलात्कार का शिकार बनाया गया और इसके बाद पुलिस ने उसके शव को जला दिया, जिससे उसकी जघन्यता और भी बढ़ गई। यह घटना न केवल मानवता के लिए एक गहरा धक्का थी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि हमारे समाज में अभी भी कितनी बड़ी दरिंदगी और अन्याय मौजूद है। इस अमानवीय कृत्य ने पूरे देश को झकझोर दिया और न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। यह दर्दनाक घटना एक कड़ा संदेश देती है कि दलितों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। समाज और सरकार को चाहिए कि वे सख्त कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि ऐसा अन्याय फिर कभी न हो।

ऐसी ही एक दर्दनाक घटना 2012 में हुई थी, जिसे हम सभी 'दामिनी कांड'(निर्भया) के नाम से जानते हैं। उस रात एक मासूम लड़की के साथ दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। उसकी चीखें आज भी हमारी आत्मा को झकझोरती हैं, जब वह अपनी इज्जत और जिंदगी के लिए उन दरिंदों से लड़ती रही। वह घटना पूरे देश के लिए एक सबक थी, एक चेतावनी कि हम कब तक चुप बैठे रहेंगे? दामिनी का संघर्ष और उसका बलिदान आज भी हमें याद दिलाता है कि हमें ऐसे अपराधों के खिलाफ खड़ा होना होगा।

लेकिन भारत में सिर्फ भारतीय महिलाएँ ही नहीं, विदेशी महिलाएँ भी सुरक्षित नहीं हैं। झारखंड के दुमका जिले में एक विदेशी महिला के साथ 7 दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया। यह महिला अपने पति के साथ बाइक से दुनिया की यात्रा कर रही थी। उनका ताल्लुक स्पेन से था, और इस यात्रा के दौरान वे अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा करती थीं। लेकिन उनके टेंट में आराम के दौरान उन पर हमला किया गया और चाकू की नोक पर उनकी इज्जत को तार-तार कर दिया गया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा देश अब बलात्कार की घटनाओं के लिए कुख्यात हो चुका है?

हर दिन देशभर में बलात्कार के लगभग 90 मामले दर्ज होते हैं। यानी हर 18 मिनट में एक महिला इस भयावह अपराध का शिकार बनती है। यह आंकड़ा 2022 का है, लेकिन आज यह और भी बढ़ चुका है। और यह तो केवल वे मामले हैं जो दर्ज होते हैं; असल में ऐसे कई मामले हैं जो अपमान और डर के कारण दर्ज ही नहीं हो पाते। अगर सभी मामले दर्ज किए जाएं, तो यह संख्या सैकड़ों में पहुंच जाएगी।

ऐसी घटनाएँ तब और गंभीर हो जाती हैं जब यह किसी विदेशी महिला के साथ होती हैं, क्योंकि तब प्रशासन, मीडिया, और समाज की नींद कुछ समय के लिए खुल जाती है। लेकिन जब हमारे देश की बेटियाँ इस प्रकार के अपराधों का शिकार होती हैं, तो उन्हें न्याय के लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ता है। फर्नांडा के मामले में भी ऐसा ही हुआ; हालांकि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है?

बलात्कार एक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या बन चुकी है। हमारे देश में दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएँ सदियों से होती आ रही हैं। आज़ादी के बाद भी इस समस्या पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। मणिपुर की घटनाओं को कौन भूल सकता है, जहाँ महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार किया गया और उन्हें नग्न घुमाया गया। ऐसी घटनाएँ हमारी न्याय व्यवस्था और प्रशासन की विफलता को उजागर करती हैं।

आज के समय में जब बलात्कार जैसे घृणित अपराध इस स्तर पर हो रहे हैं, तो हमें धर्म, संस्कृति, नैतिकता और कानून की गहराई से समीक्षा करने की आवश्यकता है। कोई पुरुष जन्म से बलात्कारी नहीं होता; वह इसी समाज में पला-बढ़ा होता है, और समाज के ताने-बाने में मौजूद विकृतियाँ उसे इस कदर अपराधी बना देती हैं।

हमारे समाज में जब एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार होता है, तो प्रशासन जाग जाता है क्योंकि इसका संबंध देश की प्रतिष्ठा से होता है। लेकिन जब देश की बेटियाँ इस तरह के अपराधों का शिकार होती हैं, तो उन्हें न्याय पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। हमें इस स्थिति को बदलने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुधार की आवश्यकता है।

बलात्कार के मामलों में सिर्फ दरिंदों को सजा देना काफी नहीं है। हमें समाज के हर वर्ग को, चाहे वह प्रशासन हो, न्याय व्यवस्था हो, या हम सभी आम नागरिक, हमें इस लड़ाई में शामिल होना होगा। तभी हम इस घिनौने अपराध से अपने समाज को मुक्त कर पाएंगे और भविष्य में किसी बेटी को यह दर्द सहना नहीं पड़ेगा।

(लेखक एक स्वतंत्र पत्रकार है)

कमला हैरिस पर अपमानजनक टिप्पणी

इंदु रानी सिंह

अमेरिका में वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं द्वारा महिलाओं के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां सुनना दुखद है, क्योंकि वे एक महिला को देश के राष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं देख सकते।
इसके अलावा, उसके पिता भारतीय और अश्वेत हैं।
भारत में अगर ऐसी टिप्पणियाँ सार्वजनिक रूप से सामने आती हैं तो चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर ये टिप्पणियाँ नेतृत्व के लिए थूकने या निगलने में बहुत मुश्किल हो जाती हैं तो एक मानक रणनीति है।
संबंधित पक्ष कहेगा कि यह उसका निजी विचार है या बेहतर होगा कि उसे 'फ्रिंज एलिमेंट' कहा जाए।
अमेरिका में ऐसी किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। अगर रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस (जिनकी पत्नी भारतीय मूल की है) उन्हें अपने खुद के जैविक बच्चे न होने के कारण 'निःसंतान कैट वूमन' कहते हैं, तो राष्ट्रपति पद के महात्वाकांक्षी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस विश्व नेताओं से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य नहीं हैं "वह एक खिलौना की तरह होंगी...वे उन्हें देखते हैं और कहते हैं 'हमें विश्वास नहीं होता कि हम इतने भाग्यशाली हैं। वे उन पर हावी हो जाते हैं। "यदि यह बात डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से नहीं कही गई होती, जो हर समय गंदगी फैलाते हैं, तो वह भारत में या कहीं और बैठकर अपना मुंह खोलते हैं। लोग सोचते कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में जनता की राय है और यही कारण है कि 1776 में देश के जन्म के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी भी कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी।
लेकिन यह सच नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी से निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन, जो 2020 में ट्रम्प को हराने के बाद चार साल तक राष्ट्रपति रहे हैं, स्वेच्छा से प्रतियोगिता से बाहर हो गए और अपनी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से 'देश के सर्वोत्तम हित' में नेतृत्व करने के लिए कहा।

और हम उनके बारे में जो जानते हैं, उसके अनुसार कमला हैरिस एक लड़ाकू और बहसबाज हैं, और नवंबर तक चलने वाले अभियान में वह ट्रम्प को कड़ी टक्कर देंगी।

लेकिन अमेरिका और भारत में महिलाओं के लिए एक बात आम है और मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं भी यह बात आम है कि अगर आप योग्यता और क्षमता में किसी महिला को नहीं हरा सकते तो

अमेरिका में वरिष्ठ नेताओं द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियाँ सुनना चिंताजनक है। कमला हैरिस जैसी योग्य महिला के बारे में रिपब्लिकन उम्मीदवार जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रम्प की टिप्पणियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि जब योग्यता और क्षमता में महिलाओं को हराया नहीं जा सकता, तो उनके चरित्र पर हमला किया जाता है। भारत और अमेरिका दोनों में महिलाओं के प्रति इस सोच का विरोध करना ज़रूरी है, ताकि समाज महिलाओं के नेतृत्व और प्रतिभा को सम्मान दे।

उसके चरित्र पर हमला करना शुरू कर दीजिए। भले ही लोग इस बकवास पर यकीन न करें, लेकिन कुछ बातें तो सच साबित होती ही हैं।
मैं अपनी पूरी ताकत से यह कहना चाहता हूँ कि महिलाएँ पुरुषों से बेहतर नेता साबित होती हैं। वे ज़्यादा समर्पित होती हैं, उनमें ज़्यादा धैर्य होता है, वे ज़्यादा व्यवस्थित होती हैं और उनका मूड नहीं बदलता।
किसी भी आदमी से पूछिए, वह यह बात स्वीकार करेगा।
दुर्भाग्य से भारत में महिलाओं को हर तरफ से लक्ष्मण रेखा से बांध दिया गया है। अगर शादी के बाद भी आपको पीटा जाए तो जोर से मत हंसिए, टिप्पणी मत कीजिए और विरोध मत कीजिए क्योंकि पुरुष हमेशा सही होता है।

इसका एक कारण यह भी है कि अगर वे विरोध करना चाहें तो उनके पास कोई सहारा नहीं है। उनका स्थान पति के घर में है और वह भगवान है।

महाभारत में पांडव पांच गांव मांग रहे थे। लेकिन एक महिला एक भी गांव नहीं मांग सकती। उन्हें संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है और वे हमेशा असुरक्षित रहती हैं। यह दुखद है क्योंकि यह एक चेन रिएक्शन है। चूंकि मां खुद सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह अपनी विवाहित बेटी पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नहीं लड़ सकती और उसे सहनशील बनने की सलाह देती है।
मैं जानता हूँ कि शिक्षा के प्रसार के साथ चीज़ें बदल रही हैं, हालाँकि बहुत धीमी गति से। जैसे-जैसे परिवार एकल होते जा रहे हैं और बच्चों की देखभाल करने के लिए दादा-दादी नहीं हैं, युवा पति-पत्नी को एहसास हो रहा है कि उनके पास सिर्फ़ खुद ही हैं।
लेकिन शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाएं शीर्ष पदों पर पहुंच रही हैं, चाहे वह सेना हो, आईएएस हो या आईपीएस हो, और आईआईएम में उनकी रैंकिंग भी अच्छी है, जिससे उन्हें हर क्षेत्र में शीर्ष प्रशासनिक पद प्राप्त हो रहे हैं।
जहां तक सर्वोच्च पद (प्रधानमंत्री) का सवाल है, दुनिया के इस हिस्से में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने दिखा दिया है कि अवसर मिलने पर महिलाएं कितनी सक्षम और निर्णायक हो सकती हैं।
भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1971 में 18 दिनों के युद्ध में पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़ दिया था, को 'महिलाओं के मंत्रिमंडल में एकमात्र पुरुष' कहा जाता था।
बेशक, उसकी अपनी कमजोरियां थीं, लेकिन क्या पुरुषों की भी अपनी सनक और इच्छाएं नहीं होतीं?
मेरा कहना यह है कि जब तक आप महिलाओं को शासन करने का मौका नहीं देंगे, तब तक आप कैसे जान पाएंगे कि वह क्या प्रतिभा ला सकती हैं?और अब समय आ गया है कि 2024 में अमेरिका को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति मिले।

लेखक: लेखक एक गैर सरकारी संगठन प्रयास के कार्यकारी निदेशक हैं।

होम्योपैथिक उपचार करके डेंगू से खुद को बचाएं

डॉ नवल कुमार वर्मा

हम इस समय बरसात के मौसम का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है तो हर जगह मच्छरों का आतंक होता है और डेंगू बुखार एक बड़ा खतरा बन जाता है। डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो मच्छरों द्वारा फैलता है, मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी प्रजाति। यह सभी उम्र के व्यक्तियों को प्रभावित करता है, लेकिन अक्सर रोगी की उम्र के आधार पर इसके लक्षण और संकेत अलग-अलग होते हैं। अलग-अलग आयु समूहों में, डेंगू को निम्नलिखित अलग-अलग लक्षणों से पहचाना जा सकता है:

शिशु एवं छोटे बच्चे :

शिशुओं और छोटे बच्चों में लक्षण तेज बुखार हो सकते हैं, लेकिन अक्सर इसे बड़े बच्चों या वयस्कों की तरह आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। फिर बुखार कम होने के बाद बारीक, चपटे दाने दिखाई दे सकते हैं। डेंगू से पीड़ित शिशु और बच्चे अक्सर असामान्य रूप से चिड़चिड़े या उधम मचाने वाले हो जाते हैं और कम भूख के साथ वे खाने से मना कर देते हैं। इसके अलावा जठरांत्र संबंधी लक्षण और खांसी और नाक बंद होना छोटे बच्चों में अधिक आम है।

यह पहचानना थोड़ा मुश्किल है कि शिशु को डेंगू है या नहीं। लगातार तेज बुखार रहना एक मुख्य संकेत है, लेकिन बहुत छोटे शिशुओं में इसका पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन व्यवहार में बदलाव जैसे कि चिड़चिड़ापन, सुस्ती या दूध पीने से मना करना खतरे के संकेत हैं। बुखार कम होने के बाद दाने निकलना भी इसका संकेत है।

2. बड़े बच्चे:-

लक्षण:-

तेज बुखार: अचानक तेज बुखार आना (अक्सर 39°C - 40°C)।

- गंभीर सिरदर्द: विशेषकर आंखों के पीछे दर्द।
- मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द: दर्द की तीव्रता के कारण इसे अक्सर "हड्डीतोड़ बुखार" कहा जाता है।
- दाने: दाने जो पूरे शरीर में फैल सकते हैं, छोटे लाल धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं।
- मतली और उल्टी: जठरांत्र संबंधी परेशानी आम है।
- थकान: अत्यधिक थकान और कमजोरी।- हल्का रक्तस्राव: जैसे नाक से खून आना या मसूड़ों से खून आना।

डेंगू के बढ़ते खतरे से रहें सतर्क:
बारिश के बाद मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे डेंगू जैसी गंभीर बीमारी फैलती है। यह मुख्यतः एडीज एजिप्टी प्रजाति के मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है, जो सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसके लक्षण उम्र के हिसाब से भिन्न हो सकते हैं, जैसे तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और दाने। इसके गंभीर लक्षणों पर ध्यान दें और समय पर इलाज कराएं।

- मान्यता:
- क्लासिक लक्षण: तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द।
- दाने: अक्सर चेहरे, अंगों और छाती पर दिखाई देते हैं।
- रक्तस्राव की प्रवृत्ति: मामूली रक्तस्राव की प्रवृत्ति पर नजर रखें, जो डेंगू के अधिक गंभीर रूप (डेंगू रक्तस्रावी बुखार) का संकेत हो सकता है।

3. वयस्क:

- लक्षण:
- तेज बुखार: अचानक तेज बुखार आना जो 2-7 दिनों तक रह सकता है।
- गंभीर सिरदर्द: आंखों के पीछे दर्द विशेष रूप से आम है।
- मांसपेशियों और जोड़ों में गंभीर दर्द: मांसपेशियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होना।
- दाने: बुखार शुरू होने के 2-5 दिन बाद लाल दाने दिखाई दे सकते हैं।
- मतली और उल्टी: सामान्य जठरांत्रिय लक्षण।
- थकान: बुखार उतरने के बाद भी लगातार थकान और कमजोरी बनी रहना।
- हल्का रक्तस्राव: जैसे नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, या आसानी से चोट लग जाना।
- मान्यता:
- तेज बुखार और दर्द: अचानक तेज बुखार के साथ तेज सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना इसके प्रमुख लक्षण हैं।
- दाने: लाल दाने जो खुजली या दर्द वाले हो सकते हैं।
- रक्तस्राव: हल्का रक्तस्राव (जैसे चोट, नाक से खून आना) भी अधिक गंभीर डेंगू की ओर बढ़ने का संकेत हो सकता है।

4. वरिष्ठ नागरिक:

- लक्षण:
- तेज बुखार: हो सकता है, लेकिन कभी-कभी कम गंभीर हो सकता है।
- गंभीर कमजोरी: थकान और कमजोरी अधिक तीव्र और लम्बे समय तक बनी रह सकती है।
- गंभीर सिरदर्द: आंखों के पीछे दर्द हो सकता है।
- मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द: युवा वयस्कों में देखे जाने वाले दर्द के समान तीव्र दर्द।
- दाने: दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वृद्ध त्वचा में कम ध्यान देने योग्य हो सकते हैं।
- गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण: मतली, उल्टी और पेट दर्द आम हैं।
- जटिलताएं: बुजुर्ग व्यक्तियों को गंभीर डेंगू होने का अधिक खतरा होता है, जिसमें डेंगू रक्तस्रावी बुखार या डेंगू शॉक सिंड्रोम शामिल है, जो रक्तस्राव, प्लाज्मा रिसाव और अंग क्षति के साथ उपस्थित हो सकता है।

- मान्यता:
- हल्का बुखार: बुखार उतना तीव्र नहीं हो सकता, लेकिन लगातार बना रह सकता है और इसके साथ काफी थकान भी हो सकती है।

- दर्द और असुविधा: सिरदर्द के साथ-साथ मांसपेशियों और जोड़ों में गंभीर दर्द की जांच करें।

- जटिलताओं का जोखिम बढ़ना: रक्तस्राव या सदमे के किसी भी लक्षण पर बारीकी से नजर रखें, विशेष रूप से उन लोगों में जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या हो।

गंभीर डेंगू के सामान्य चेतावनी संकेत (सभी आयु वर्ग में):

- पेट में तेज दर्द.
- लगातार उल्टी होना।
- तेजी से सांस लेना.
- मसूड़ों या नाक से खून आना।
- थकान, बेचैनी या चिड़चिड़ापन।
- उल्टी या मल में खून (काला, तार जैसा मल)।
- सदमे के लक्षण (ठंड, चिपचिपी त्वचा, तेज़ नाड़ी)।

अंत में हम कह सकते हैं कि डेंगू बुखार की पहचान मुख्य रूप से तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और दाने के दिखने के संयोजन पर आधारित होती है। हालाँकि, उम्र के हिसाब से लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं, शिशुओं और बुजुर्गों में संभावित रूप से लक्षण अधिक सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं। जटिलताओं को रोकने के लिए, विशेष रूप से गंभीर मामलों में, प्रारंभिक पहचान और उचित चिकित्सा देखभाल महत्वपूर्ण है।

डेंगू की रोकथाम और उपचार के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए:

1. होम्योपैथिक दवाएं :

2.

- रोगनिरोधी उपचार: डेंगू बुखार के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में निम्नलिखित विशिष्ट होम्योपैथिक उपचार की सिफारिश की जाती है। इन सामान्य उपचारों में शामिल हैं:

- यूपेटोरियम परफोलिएटम 200: इसे अक्सर निवारक उपाय के रूप में सुझाया जाता है। डेंगू के प्रकोप के दौरान सप्ताह में एक बार यूपेटोरियम परफोलिएटम 200 की खुराक लेने से वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

- ब्रायोनिया 30 और जेल्सीमियम 30 इन दवाओं को निवारक उपाय के रूप में एक सप्ताह तक प्रतिदिन बदल-बदल कर इस्तेमाल किया जा सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां डेंगू का प्रकोप अधिक है।

2. डेंगू के दौरान होम्योपैथिक उपचार:

- यूपेटोरियम परफोलिएटम: यह दवा तेज बुखार, शरीर में तेज दर्द और हड्डियों में दर्द जैसे लक्षणों को ठीक करने में बहुत कारगर है, जो डेंगू बुखार की खासियत है। इसे तीव्र चरण के दौरान दिन में तीन बार 30C शक्ति में लिया जा सकता है।

- जेल्सीमियम: बुखार के साथ अत्यधिक थकान, चक्कर आना, पलकों में भारीपन महसूस करने वाले मरीजों को जेल्सीमियम 30 हर 4 घंटे में लिया जा सकता है।

- आर्सेनिकम एल्बम: यदि रोगी को कमजोरी के साथ दस्त या उल्टी जैसे जठरांत्र संबंधी लक्षण हों, तो आर्सेनिकम एल्बम 30 हर 3-4 घंटे में दिया जा सकता है।

बुजुर्गों और बच्चों में डेंगू के लक्षण:
शिशुओं और छोटे बच्चों में डेंगू के लक्षण पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन तेज बुखार और चिड़चिड़ापन प्रमुख संकेत हैं। वहीं, बुजुर्गों में कमजोरी और थकान अधिक देखी जा सकती है। बुजुर्गों को डेंगू शॉक सिंड्रोम और रक्तस्रावी बुखार जैसी जटिलताओं का अधिक खतरा होता है। किसी भी गंभीर लक्षण पर तुरंत चिकित्सा सलाह लें।

- इपेकाकुआन्हा: लगातार मतली और उल्टी के मामलों में, इपेकाकुआन्हा 30 को हर 3 घंटे में दिया जा सकता है।

- फॉस्फोरस: प्लेटलेट काउंट में महत्वपूर्ण गिरावट होने पर इस उपाय की सिफारिश की जाती है। शरीर की रिकवरी में सहायता के लिए फॉस्फोरस 30 को दिन में दो बार लिया जा सकता है।

3. स्वास्थ्य लाभ के लिए होम्योपैथिक सहायता:

- कैरिका पपीता (पपीता पत्ती का अर्क): डॉ. नवल का सुझाव है कि होम्योपैथिक रूप में उपलब्ध पपीता पत्ती का अर्क प्लेटलेट काउंट और रिकवरी में सुधार करने में सहायक हो सकता है। इसे मदर टिंचर के रूप में (पानी में 10 बूंदें, दिन में दो बार) या होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार लिया जा सकता है।

- चाइना ऑफिसिनेलिस: डेंगू के बाद कमजोरी और थकावट से उबरने के लिए, जीवन शक्ति को बहाल करने के लिए चाइना 30 को एक सप्ताह तक प्रतिदिन एक बार लिया जा सकता है।

4. सामान्य दिशानिर्देश:

- होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श: व्यक्तिगत उपचार योजनाओं के लिए योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करना आवश्यक है, खासकर यदि लक्षण बिगड़ जाते हैं या जटिलताएं उत्पन्न होती हैं।

- पारंपरिक चिकित्सा के साथ संयोजन: होम्योपैथिक उपचार का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा देखभाल के साथ, स्वास्थ्य पेशेवरों की देखरेख में किया जा सकता है।

इन होम्योपैथिक उपचारों को पारंपरिक निवारक उपायों और आहार प्रबंधन के साथ एकीकृत करके, डेंगू की रोकथाम और उपचार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है। यह संयुक्त रणनीति लक्षणों की गंभीरता को कम कर सकती है और तेजी से ठीक होने में सहायता कर सकती है।

डेंगू की रोकथाम के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों पर कार्य किया जाना चाहिए:

मच्छर नियंत्रण उपाय:

- प्रजनन स्थलों को हटाएँ: नियमित रूप से कंटेनरों, फूलों के गमलों, बाल्टियों, टायरों और अन्य स्थानों पर खड़े पानी की जाँच करें और उसे हटाएँ, जहाँ मच्छर प्रजनन कर सकते हैं।

- मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग करें: खुली त्वचा और कपड़ों पर डीईईटी-आधारित या प्राकृतिक मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग करें।

- सुरक्षात्मक कपड़े पहनें: त्वचा के संपर्क को कम करने के लिए लंबी आस्तीन वाली शर्ट, लंबी पैंट, मोजे और जूते पहनें।

- मच्छरदानी और स्क्रीन लगाएं: मच्छरों को बाहर रखने के लिए बिस्तरों पर जाली और खिड़कियों और दरवाजों पर स्क्रीन का उपयोग करें, विशेष रूप से मच्छरों की अधिकतम सक्रियता के समय (सुबह और शाम) के दौरान।

- कीटनाशक का छिड़काव: यदि संभव हो तो, मच्छरों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव करें, तथा

घर के अंदर वाले स्थानों और उन स्थानों पर विशेष ध्यान दें जहां मच्छर रहते हैं।
2. सामुदायिक भागीदारी:
- जन जागरूकता अभियान: मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने और सुरक्षात्मक उपायों के महत्व के बारे में समुदायों को शिक्षित करें।
- सामुदायिक सफाई अभियान: पड़ोस से संभावित प्रजनन स्थलों को हटाने के लिए नियमित सफाई अभियान आयोजित करें।
- सरकार और स्वास्थ्य विभाग समन्वय: मच्छरों की आबादी की निगरानी और नियंत्रण के लिए स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग सुनिश्चित करें।
3. व्यक्तिगत सुरक्षा:
- मच्छरों की चरम सक्रियता से बचें: सुबह जल्दी और दोपहर बाद के समय घर के अंदर रहें, जब एडीज मच्छर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
- एयर कंडीशनिंग का उपयोग करें: यदि संभव हो तो एयर कंडीशनिंग का उपयोग करें, क्योंकि इससे मच्छरों की सक्रियता कम हो जाती है।
डेंगू बुखार से पीड़ित लोगों को निम्नलिखित आहार दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए:
1. जलयोजन:
- तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएँ: बुखार और उल्टी के कारण होने वाले निर्जलीकरण को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएँ, जैसे पानी, नारियल पानी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस), हर्बल चाय और ताजे फलों का रस।

- इलेक्ट्रोलाइट संतुलन: निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को रोकने के लिए इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करने वाले पेय, जैसे ओआरएस, को शामिल करें।
2. पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ:
- उच्च कैलोरी वाले, आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ: अपने आहार में हल्के, मुलायम खाद्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी, उबली हुई सब्जियां, सूप और स्टू शामिल करें जो पेट के लिए आसान हों।
- प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ: रिकवरी में सहायता के लिए उबले अंडे, टोफू, पनीर या फलियां जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें।
- विटामिन सी: प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और आयरन के अवशोषण में सहायता के लिए संतरे, नींबू और अंगूर जैसे खट्टे फलों का सेवन करें।
- आयरन युक्त खाद्य पदार्थ: डेंगू के रोगियों में होने वाले एनीमिया को रोकने के लिए पालक, अनार और लाल मांस (संयमित मात्रा में) जैसे खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें।
- पपीते के पत्ते का रस: कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि पपीते के पत्ते का रस प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद कर सकता है, हालांकि इसे सावधानी के साथ और चिकित्सकीय देखरेख में लिया जाना चाहिए।
3. किन खाद्य पदार्थों से बचें:

डेंगू से बचाव के उपाय:
डेंगू से बचने के लिए मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करना और व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। घर और आसपास के क्षेत्रों में खड़े पानी की सफाई, मच्छरदानी का इस्तेमाल, और मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग करें। सामुदायिक सफाई और जागरूकता अभियान भी डेंगू की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

- तैलीय और तले हुए खाद्य पदार्थ: भारी, चिकने या तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें, क्योंकि उन्हें पचाना कठिन हो सकता है और मतली को बढ़ा सकता है।
- मसालेदार भोजन: मसालेदार भोजन का सेवन सीमित करें क्योंकि इससे पेट की परत में जलन हो सकती है।
- कैफीनयुक्त और शर्करायुक्त पेय: कॉफी, सोडा और ऊर्जा पेय जैसे पेय से बचें, जो शरीर को निर्जलित कर सकते हैं और लक्षणों को बदतर बना सकते हैं।
डेंगू बुखार से पीड़ित व्यक्ति और उसकी देखभाल करने वालों को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
1. चिकित्सा देखभाल:
- तत्काल चिकित्सा सहायता लें: यदि डेंगू बुखार का संदेह हो तो तुरंत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श लें।
- नियमित निगरानी: गंभीर पेट दर्द, लगातार उल्टी, तेज़ सांस लेना, मसूड़ों से खून आना या थकान जैसे चेतावनी संकेतों पर नज़र रखें, जो गंभीर डेंगू (डेंगू रक्तस्रावी बुखार) का संकेत हो सकते हैं।
- रक्त परीक्षण: चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित रूप से प्लेटलेट काउंट, हेमेटोक्रिट स्तर और लिवर फंक्शन परीक्षण करवाएं।
2. लक्षणात्मक उपचार:
- बुखार कम करने और दर्द से राहत पाने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सकों के दिशा-निर्देशों के अनुसार यूपेटोरियम पर्फ 200, जेल्सीमियम 200 या ब्रायोनिया 200 जैसी होम्योपैथिक दवाएँ लें। एस्पिरिन या इबुप्रोफेन जैसी NSAIDs से बचें क्योंकि वे रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकती हैं।
- आराम: शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और रिकवरी को समर्थन देने के लिए पूर्ण आराम सुनिश्चित करें।
- अत्यधिक परिश्रम से बचें: थकान और प्रतिरक्षा प्रणाली को और अधिक कमजोर होने से बचाने के लिए शारीरिक गतिविधि सीमित करें।
3. जटिलताओं की निगरानी:
- प्लेटलेट काउंट की निगरानी: प्लेटलेट के स्तर की नियमित निगरानी करें क्योंकि प्लेटलेट काउंट में गिरावट से जटिलताएं हो सकती हैं।
- जलयोजन निगरानी: सुनिश्चित करें कि रोगी पर्याप्त रूप से जलयुक्त है, मूत्र उत्पादन और निर्जलीकरण के अन्य लक्षणों की निगरानी करें।
4. अस्पताल में भर्ती होने के मानदंड:
- गंभीर लक्षण: यदि लक्षण बिगड़ जाएं या गंभीर डेंगू का संदेह हो, तो करीबी निगरानी और सहायक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो सकता है।
- अंतःशिरा तरल पदार्थ: गंभीर मामलों में, जलयोजन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए अंतःशिरा तरल पदार्थ की आवश्यकता हो सकती है।
अंत में हम कह सकते हैं कि डेंगू बुखार को रोकने के लिए मुख्य रूप से मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करना और व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपाय करना शामिल है। यदि संक्रमित हो, तो उचित चिकित्सा देखभाल, सहायक आहार और करीबी निगरानी के माध्यम से स्थिति का प्रबंधन करना ठीक होने और जटिलताओं को रोकने के लिए आवश्यक है।

लेखक परिचय: डॉ. नवल कुमार वर्मा, एमडी (होम्योपैथी), पीएचडी, और डॉक्टर ऑफ साइंस होम्योपैथी के एक प्रख्यात विद्वान हैं।

माँ की ममता का मारा एक खूंखार डाकू

लेखक दिनेश वर्मा के बारे में

लेखक, दिनेश एन वर्मा, भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी हैं, जो बार में कुछ समय बिताने के बाद भारत सरकार में शामिल हो गए, जिसे उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद फिर से संभाला। सरकार में रहते हुए, भारतीय जनसंचार संस्थान में शुरुआती पंद्रह महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, श्री वर्मा ने अपनी सरकारी सेवा के चौंतीस वर्षों के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया विंग में विभिन्न पदों पर अपनी पोस्टिंग की। हालाँकि उन्होंने सरकार में रहते हुए लिखना शुरू किया, लेकिन अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना दिल और आत्मा इसमें लगा दी और 2016 में पीपुल्स सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित अपनी पहली किताब 'माई टाइम्स माई टेल्स' से इसकी शुरुआत की, जो बरेली, यूपी से दिल्ली के हलचल भरे महानगर तक की उनकी यात्रा के दौरान हुई घटनाओं और प्रकरणों पर आधारित सत्ताईस कहानियों का संग्रह है। श्री वर्मा ने 'ए फैसिनेटिंग ट्रिप टू ह्यूमन्स मैन्युफैक्चरिंग साइट' लिखने में दूसरा प्रयास किया, जो स्पष्ट रूप से एक अवधारणा पुस्तक थी जो मनोरंजक तरीके से मानवीय स्थिति पर एक अभिनव नज़र डालती है। लघु कथाओं और लेखों 'मेरे समय की मेरी कहानियां' के हिंदी संस्करण के प्रकाशन के बाद, हाल ही में प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक 'द ब्लेस्ड कर्स' पाठकों, विशेषकर युवाओं को स्वतंत्रता के आसपास के वर्षों में ले जाने की उनकी दीर्घकालिक इच्छा का परिणाम है, ताकि वे अपने पूर्वजों के दैनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से परिचित हो सकें।

संलग्न कथा उनकी पुस्तक मेरे समय की मेरी कहानियाँ से ली गयी

- संपादक

यकायक जोर का शोर उठा और बाजार में भगदड़ सी मच गई। जैसे ही किसी ने कहा, "वह यहीं है!" मेरा हाथ बिजली की गति से सिर पर गया, और मैंने तुरंत अपनी पुलिस की टोपी उतारकर छिपा ली। यह कहते हुए छोटे बब्बा अचानक खामोश हो गए।

कहानी का शीर्षक: लचीला पत्थर

हम सभी, कुछ मित्र और मैं, छोटे बब्बा के इर्द-गिर्द बैठे हुए थे। उनसे डाकुओं और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ों की रोमांचक कहानियाँ सुनने का मौका हमारे लिए हमेशा खास होता था। छोटे बब्बा, जो मेरे दादी के छोटे भाई थे, मुरैना जिले के एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। जब भी वह छुट्टियों में हमारे यहाँ आते, यह हमारे लिए बेहद ख़ुशी का समय होता था। उनके पास बीहड़ों के बीच की अनेकों कहानियाँ थीं, जिन्हें वह सजीव अंदाज में सुनाते थे। हम सभी मित्र उन्हें घेरकर बैठ जाते और अपने-अपने प्रश्नों की झड़ी लगाते।

इस बार जब उन्होंने अचानक अपनी बात रोक दी, तो हम सभी बेचैन हो गए। हम सभी ने उनसे ज़िद करना शुरू कर दिया कि आखिर उन्हें अपनी पुलिस की टोपी क्यों छुपानी पड़ी।

छोटे बब्बा ने अनमने ढंग से कहा, "क्या बताऊं बच्चों, हम पुलिस वाले डाकू मानसिंह से बहुत डरते थे। वह उस इलाके का सबसे बड़ा डाकू था। न केवल वह खुद कद्दावर और ख़ूंख़ार था, बल्कि उसका गैंग भी उतना ही क्रूर और निर्दयी था। लोग उसकी दहशत से कांपते थे, लेकिन एक अजीब बात थी। लोग उसे राजा जैसा मानते थे। गरीबों की मदद करता था और उन्हें हमेशा न्याय दिलाने के लिए खड़ा रहता था।"

"तो फिर आपको टोपी क्यों छुपानी पड़ी?" एक मित्र ने सवाल दोहराया।

छोटे बब्बा ने हंसते हुए कहा, "उस दिन जल्दी में मैं पैजामा और कमीज़ पहने सब्ज़ी मंडी चला गया था। टोपी उतारना भूल गया। जैसे ही किसी ने मानसिंह के बारे में शोर मचाया, मुझे अपनी जान का डर सताने लगा और मैंने टोपी उतार कर छुपा ली।"

इस बीच एक और सवाल उठ गया, "बब्बा जी, क्या सभी डाकू इतने ही क्रूर होते हैं?"

छोटे बब्बा कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, "देखो बच्चों, डाकू भी इंसान ही होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही ज़ालिम होते हैं, और वे जब बीहड़ों में चले जाते हैं तो क्रूरता उनकी पहचान बन जाती है। लेकिन कुछ लोग समाज की क्रूरता से तंग आकर बीहड़ों में उतरने को मजबूर हो जाते हैं। सारे डाकू इतने क्रूर नहीं होते। उनमें भी कुछ कोमल हृदय के होते हैं, जो बाहर से कठोर दिखते हैं, लेकिन अंदर से नरम होते हैं।"

हम सब यह सुनकर हैरान रह गए। क्या सच में डाकू कोमल हृदय के भी होते हैं? छोटे बब्बा ने हमारी जिज्ञासा को समझा और हमें एक ऐसे ही डाकू की कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गए। वह कहानी सुनाते समय हमें ऐसा लगा जैसे हम सब खुद उस घटना का हिस्सा बन गए हों।

छोटे बब्बा ने कहना शुरू किया, "ठक-ठक-ठक! दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़ा एक वृद्ध महिला ने खोला। बाहर खड़ा व्यक्ति उसे घूर रहा था, मानो उसे किसी चीज़ की प्रतीक्षा हो। महिला ने पीछे मुड़कर उसे अंदर आने का रास्ता दिया और खुद चूल्हे की ओर बढ़ गई। वह व्यक्ति आंगन के किनारे पर खड़ा रहा, और महिला ने कुछ रोटियाँ लाकर उसके

हाथों में रख दीं। वह बिना कुछ कहे झटपट उन रोटियों को लेकर चला गया।"

"यह व्यक्ति कोई और नहीं, इलाके का मशहूर डाकू धनुआ था। वह रोज़ इसी तरह आता, रोटियाँ लेकर चला जाता। स्टेशन मास्टर शम्भुनाथ, जो उस घर के मालिक थे, यह नज़ारा देख रहे थे। वह समझ चुके थे कि यह डाकू धनुआ ही था, जिसके बारे में उन्होंने पहले केवल सुना था। धनुआ अकेला डाकू था, जो बिना किसी शोर-शराबे के अपने काम को अंजाम देता था। वह छतों से छलांग लगाता, दीवारों पर चढ़ जाता, और कभी भी किसी का नुकसान नहीं करता था।"

छोटे बब्बा ने आगे बताया, "धनुआ किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन उसकी मौजूदगी में डर स्वाभाविक था। उसे पकड़ने के लिए कई बार पुलिस ने योजनाएं बनाईं, लेकिन वह हमेशा बच निकलता। उसकी तेज़ गति और सूझबूझ के कारण उसे पकड़ना मुश्किल था।"

छोटे बब्बा ने एक और रोचक किस्सा सुनाया। "धनुआ को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक नई योजना बनाई। इस बार ट्राली पर रेलवे पटरियों का निरीक्षण होना था। ट्राली में पुलिसकर्मियों को छिपा दिया गया, और जैसे ही ट्राली धनुआ के पास से गुज़री, पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन धनुआ इतना तेज़ था कि वह हाथों से फिसलकर गायब हो गया।"

इस किस्से ने हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया। कैसे कोई इंसान इतना तेज़ और चालाक हो सकता है? धनुआ की ये बातें सुनकर हम सबके मन में उसके प्रति एक अजीब सा सम्मान और भय दोनों पैदा हो गया था।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। छोटे बब्बा ने आगे कहा, "धनुआ को पकड़ने के लिए पुलिस ने और भी जाल बिछाए। लेकिन हर बार वह बच निकलता। एक दिन, पुलिस ने एक और चाल चली। ट्राली में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी बैठे और जैसे ही ट्राली धनुआ के करीब पहुंची, वे उस पर झपट पड़े। इस बार धनुआ की चालाकी काम नहीं आई, और उसे पकड़ लिया गया। उसे हथकड़ियाँ पहनाई गईं और ट्राली में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया।"

यह कहानी सुनकर हम सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना तेज़ और चालाक व्यक्ति आखिर कैसे पकड़ा गया। छोटे बब्बा ने बताया कि धनुआ ने खुद को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। वह शांत बैठा रहा और केवल स्टेशन मास्टर शम्भुनाथ को घूरता रहा, जिसने उसे पकड़वाने में मदद की थी।

डाकू भी इंसान होते हैं" छोटे बब्बा की रोमांचक कहानियाँ बीहड़ों के उन खतरनाक पलों को जीवंत कर देती हैं, जहाँ पुलिस और डाकुओं के बीच संघर्ष होता है। लेकिन क्या डाकू केवल क्रूर होते हैं? पढ़ें छोटे बब्बा के अनुभवों से धनुआ की कहानी, जो दिखाती है कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है।

छोटे बब्बा ने कहा, "धनुआ ने एक शब्द कहा, 'तुम्हऊ टेसन माटर।' यह सुनकर शम्भुनाथ सिहर उठे। लेकिन धनुआ ने कोई और हरकत नहीं की। कुछ देर बाद, जब ट्राली स्टेशन पहुंची, तो एक अजीब बात हुई। धनुआ ने एक झटके में अपनी हथकड़ियाँ तोड़ दीं और बिना कुछ कहे वहां से भाग निकला। पुलिसकर्मी सकते में आ गए और उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।"

यह घटना हमें और भी चकित कर गई। कैसे एक इंसान इतनी आसानी से हथकड़ियाँ तोड़ सकता है? छोटे बब्बा ने कहा, "धनुआ इंसान होते हुए भी कुछ अलग था। उसकी ताकत और सूझबूझ उसे बाकी डाकुओं से अलग बनाती थी।"

धनुआ की कहानी ने हमारे मन में अनेकों सवाल पैदा कर दिए। क्या वाकई में सभी डाकू इतने खतरनाक होते हैं? क्या उनमें भी कोमलता होती है? क्या समाज की क्रूरता ही उन्हें डाकू बनाती है?

छोटे बब्बा की इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है। चाहे वह डाकू हो या पुलिसकर्मी, हर किसी के अंदर मानवीय भावनाएं छिपी होती हैं। धनुआ जैसे लोग, जो समाज से कटे हुए होते हैं, कभी-कभी खुद को उस समाज का हिस्सा नहीं मानते।

कहानी खत्म होते ही हम सब चुप हो गए। छोटे बब्बा के चेहरे पर एक गंभीरता थी, जैसे वह हमें कुछ सिखा रहे हों। उन्होंने अंत में कहा, "डाकू भी इंसान होते हैं। उनके अंदर भी डर, क्रोध, प्यार और सम्मान होता है। समाज का व्यवहार कभी-कभी उन्हें उस राह पर ले जाता है, जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है।"

हम सब छोटे बब्बा की बातों को सोचते रहे। धनुआ की कहानी हमारे लिए सिर्फ एक रोमांचक किस्सा नहीं थी, बल्कि वह इंसानी जज़्बात और समाज की जटिलताओं को समझने का एक माध्यम थी। उस दिन हमें यह अहसास हुआ कि दुनिया में कुछ भी केवल काला या सफेद नहीं होता। हर इंसान की अपनी कहानी होती है, जो उसे दूसरों से अलग बनाती है।

पुस्तक समीक्षा

व्यंग्य संग्रह “दस हाथ वाला आदमी”

हुकम सिंह “ज़मीर”

दस हाथ वाला आदमी” कृति आज के हताश व निराश युवाओं में एक उर्जा का संचार कर सकती है।—

अब साहब, दस हाथ वाले आदमी से दो हाथ वाला आदमी दो दो हाथ करेगा तो परिणाम क्या होगा ये तो पहले से तय है। लेकिन उपाध्याय जी ने व्यंग्य में भी ऐसी तरंग छेड़ दी कि मन की उमंग कुलाचे भरती रही और जीवन के गम्भीर विषयों व परिस्थितियों को भी सहज बना दिया है। तो ये दो हाथ वाला आदमी भी दस हाथ वाले आदमी से दो दो हाथ करता रहा। निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये शक्ति दस हाथ वाले आदमी से ही मिली।

साहित्यिक रूप से ये कृति एक व्यंग्य संग्रह है लेकिन मेरी दृष्टि में इसे व्यंग्य संग्रह कहना भी एक व्यंग्य ही है। व्यावहारिक अर्थ में ये एक व्यक्ति की कार्य क्षमता का प्रतीक है जो अपनी कर्तव्यनि

ष्ठा के दम पर हंसते—हंसते अर्थात बहुत सहजता से अकेले ही अनेक व्यक्तियों के कार्यो को अपनी पूरी दक्षता व निपुणता से उच्चतम परिणाम दे सकता है।

छोटी—छोटी क्षणिकाओं में हंसिकाएं यूं छिपी हुई हैं जैसे नभ की तारिकाओं की मंद—मंद हंसी छलक कर बरसती हुई किसी बगीचे में शाखों के गर्भ से अभी—अभी निकली कलियों में आ कर छिप गयी हो।

हां, उपाध्यायजी ने एक अच्छा काम किया कि इस कृति का नाम दस हाथ वाला आदमी रखा, दस सिर वाला आदमी या

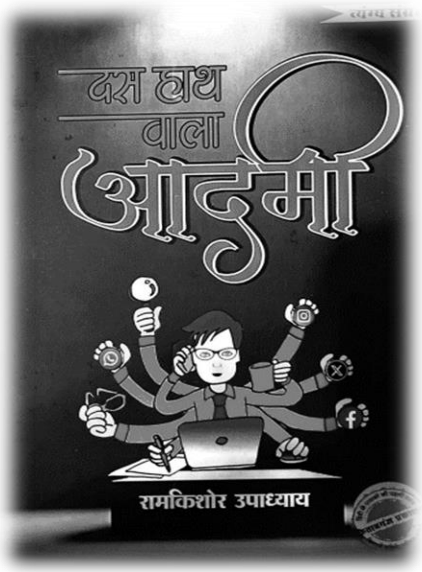

सहस्त्रबाहू नहीं। एक ही सिर में असीम संभावनाओं के साथ मनुष्य की व्यावहारिक शारीरिक क्षमता के दृष्टिगत तीन—तीन सिर व चारभुजाधारी रूप में भी अनेक अवसरों पर विवश देवता और भगवानों के समक्ष मात्र दो हाथ वाले आदमी की क्षमताओं का ये अंकन निश्चित रूप से पठनीय व संग्रहणीय है। ऐसी कृतियां आज के हताश व निराश युवाओं में एक उर्जा का संचार कर सकती है।

मैं उपाध्यायजी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उनकी इस कृति में उनके व्यक्तित्व को दो पंक्तियों में कहूं तो ...

दर्द में भी मुझको मुस्कुराने का हुनर आता है,

तू न हो मुझपे मेहरबां बला से अगर न हो।।

वरिष्ठ साहित्यकार

आनंदपुरी,जयपुर ,राजस्थान

हास्य व्यंग क्षणिका

गधों को ही डॉक्टरेट !

"फ़्रांस में डॉक्टरेट बहुत सस्ती हो गई थी। कोई 500 फ़्रैंक विश्वविद्यालय को भेज दे और मनचाहे विषय पर डॉक्टरेट ले ले। एक रईस ने 8-10 विषयों पर डॉक्टरेट ले ली। वो अपने घोड़े को बहुत प्यार करता था। उसने विश्वविद्यालय को 500 फ़्रैंक भेजे और लिखा कि मेरे घोड़े को भी एक डॉक्टरेट दे दी जाए। विश्वविद्यालय से जवाब आया : हम घोड़ों को डॉक्टरेट नहीं देते। सिर्फ़ गधों को देते हैं।"

~ हरिशंकर परसाई

पुस्तक समीक्षा

मिथकों से विज्ञान के सफर के अनबूझे रास्ते

डॉ मुज़फ्फर हुसैन ग़ज़ाली

*(डॉ. गौहर रजा एक लेखक, कवि, फिल्मकार और वैज्ञानिक हैं । हाल ही में प्रकाशित उनकी पुस्तक "मिथकों से विज्ञान तक" पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई। इस चर्चा में डॉ. मुज़फ्फर हुसैन गज़ाली ने डॉ रजा से उनकी पुस्तक के मुख्य बिंदुओं, ब्रह्मांड के विकास, मानव उत्पत्ति, सभ्यता की शुरुआत, और चाँद-सूरज के देवता होने की अवधारणाओं पर विस्तृत बातचीत की। डॉ रजा ने विज्ञान की परिभाषा और उसकी जटिलताओं को स्पष्ट करने के साथ-साथ, विभिन्न सभ्यताओं में ब्रह्मांड के विकास पर उनके दृष्टिकोण को भी साझा किया । इस बातचीत के माध्यम से, उन्होंने विज्ञान और मिथक के बीच के अंतर को समझाने का प्रयास किया है। - **संपादक**)*

प्रश्न - गौहर राजा साहब आप की पुस्तक का खास बिंदु क्या है ?

उत्तर - इसमें मैंने ये कोशिश की है कि इस किताब में तारीफ, जिसे हम डेफिनिशन कहते हैं वह साइंस की पेश करने की कोशिश करूँ। ये बहुत मुश्किल सवाल मुझे हमेशा से परेशान करता रहा। जब मैं साइंस पढ़ रहा था तो मुझे मालूम था के डेफिनिशन्स यानी तारीफ या परिभाषा जो है वह साइंस में बहुत अहमियत रखती है। खुद साइंस की परिभाषा अपने अंदर इतनी मुश्किल है। यह धीरे-धीरे पता लगना शुरू हुआ। क्योंकि ये बहस हमारे समाज के अंदर भी चलती है कि किसे हम साइंस कहे, किसे साइंस नहीं कहें? बड़े सारे दावे किए जाते हैं कि हमारी किताबों में साइंस है, हमारे पुराणों में साइंस है, हमारे शास्त्रों में साइंस है, हमारे धर्म शास्त्रों में साइंस है। दूसरी ओर जब में ने शोध करना शुरू किया कि दार्शनिक, इतिहासकार क्या कहते हैं तब मुझे मालूम हुआ कि यह एक कठिन सवाल है। क्योंकि कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं थी जिस पर सब सहमत हो। मैं ने इस किताब मैं यह कोशिश की है कि लोग समझ पाएं कि साइंस क्या है। उसका मेरे सामने एक ही तरीका था कि यह बताया जाये कि साइंस की तमाम परिभाषाएं खंगाल कर वह परिभाषित करूँ जो साइंस नहीं है। क्यूंकि जब तक हम यह परिभाषित नहीं करेंगे तब तक साइंस को भी परिभाषित नहीं किया जा सकता।

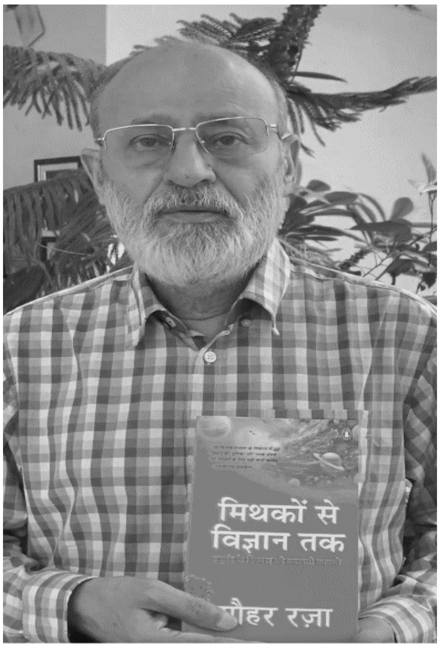

प्रश्न - ब्रह्मांड के विकास की कहानी किस प्रकार बदल रही है इस पर भी प्रकाश डालिये ?

उत्तर - एक ओर हमें अफ्रीका से कहानियां मिलीं यानी जनजातियों की कहानियां थीं, ट्राइबल्स की कहानियां थीं, हमको मेस्सोपोटामिया में, ईजिप्ट में, अपनी सभ्यता में, भारत की सभ्यता में, चीन की सभ्यता में या यूनान की सभ्यता में हम को इस सवाल का जवाब लगातार मिलता है कि ये ब्रम्हांड क्या है? इंसान इस धरती पर क्यों हैं? सूरज चाँद सितारे कैसे पैदा हुए? ये सवाल इंसान को लगातार परेशान करता रहा, पूरी ह्युमानिटी को करता रहा। तो एक तरफ तो हमारे पास ये कहानियां हैं, जिनमें मुझे लगा कि अगर हम इन कहानियों को इन मिथकों को देखना शुरू करें तो इनमें बदलते हुए समाज की वजह से ये कहानियां मुझे बदलती हुई दिखाई देती हैं। और जो हमारे शास्त्रों में हमारी किताबों में, हमारे धर्मों में जो कहानियां हैं उनकी जड़े भी बहुत पुरानी दिखाई देने लगीं। यानी वह बदलती हुई, धीरे - धीरे जैसे जैसे समाज बदलता रहा वैसे वैसे उन कहानियों में कुछ बदलाव आते रहे, कुछ नई चीज़े पैदा होती रहीं।

अगर हम एक उदाहरण लें कि जब तक एक राजा की कल्पना नहीं है तब तक इन कहानियों में हमे एक खुदा की कल्पना भी दिखाई नहीं देती है। यानी एक ब्रह्मा का तसव्वर हमको दिखाई नहीं देगा। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग देवता दिखाई देते हैं। किसी देवता ने पैदा किया कोई देवता चला रहा हैं, कोई देवता वर्षा कर रहा है और कोई अन्न उगा रहा है। मगर जब समाज बदला और औरत का दर्जा मर्द के मुकाबले में कम हो गया और उनके ऊपर कंट्रोल बढ़ा तो ईजिप्ट में एक राजा पैदा हुआ जो औरतों की समस्याओं का राजा या देवता कहलाया। एक ओर धीरे धीरे ये कहानियां बदलीं और दूसरी तरफ साइंस की बदलती हुई कहानियां थीं यानी पहले कहा गया पृथ्वी चपटी है। फिर उसके बाद पृथ्वी गोल हो गयी। सूरज, चाँद, सितारे उसके चारो तरफ चक्कर लगाने लगे। पहले तो एक तरफ से निकलते थे, दूसरी तरफ डूब जाते थे लेकिन जैसे ज़मीन गोल हुई वो पूरा चक्कर लगाने लगे। अब ज़मीन ब्रम्हांड के केंद्र में आ गयी, केंद्र से निकल कर कॉपर निकस के दौर के बाद वह केंद्र भी ख़त्म हो गया। अब सवाल ये था की ये सब कुछ चल कैसे रहा है? अगर इसका कोई केंद्र ही नहीं है, तो फिर कहा गया कि सब कुछ जो चल रहा है वे गुरुत्वाकर्षण की वजह से चल रहा है। जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं

और फिर यहाँ तक बात पहुंची के पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात जो है वो फैली हुयी है बहुत दूर तक लेकिन वो स्थिर है, रुकी हुई है और आइंस्टाइन जैसे बड़े दिमाग ने उन लोगों का मजाक उड़ाया जो कह रहे थे की फैल रही हैं ज़मीन। लेकिन एडविन हबल जैसे लोगों ने जब ये साबित कर दिया की ये पूरा ब्रह्मांड फैल रहा तो फिर आइंस्टाइन को माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने माफी मांग ली। तो साइंस के अंदर गलती करना और उसको मानना एक बड़ी बात है। बदलाव लगातार होते रहना, ये एक बड़ी बात है। हर चीज़ को बार बार परखना, चाहे सवाल वही हो और उसका जवाब नई अगर जानकारी आ जाए तो वो बदल करके लोगों के सामने समझने की कोशिश करके उसको पेश करना यह है इस ब्रह्माण्ड की बदलती हुई कहानी।

प्रश्न - सवाल यह है कि मनुष्य की उत्पत्ति किस तरह हुई? कहते हैं पहले वह बंदर की शकल में था, फिर आदिमानव बना और अब उसकी विकसित शकल वह है जिसमे आप और मैं हैं इस के पीछे की क्या कहानी है?

उत्तर - मैंने वैसे तो इस किताब की शुरुआत ही एक गद्य नज़्म से की है जिसमे यही कहानी है कि हम कैसे पैदा हुए और इस धरती के ऊपर ज़मीन के ऊपर जो साइंस कह रहे हैं। मैं धर्मों की बात नहीं कर रहा धर्मों में अपनी अपनी कहानियां हैं। साइंस की जो कहानी है वह ये कह रही है कि इस धरती के ऊपर ज़िन्दगी पैदा हुई, इस धरती की जिसकी अपनी ज़िन्दगी 4.5 बिलियन वर्ष के करीब है तो उसके एक बिलियन वर्ष के अन्दर ज़िन्दगी पैदा हुई। ज़िन्दगी ने शक्ले बदली तरह तरह के जानवर आये, तरह तरह की उनकी जातियां पैदा हुईं जानवरों की, जिन्हें हम प्रजातियां कहते हैं। उनमे बदलाव आते आते लगभग 3.5 बिलिय वर्ष में कुदरत ने उसे एक बेहतरीन शकल दी। जो हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है, जिसे हम इंसानी दिमाग कहते हैं। जहाँ तक सवाल इसका है कि हम कहाँ से आए यानी इंसान कहाँ से आया उसमें साइंस की आज की अंडरस्टैंडिंग है डार्विनिज़्म या विकास के उसूलों पर, आज का जो मानव है, आज का जो इंसान है वह लगभग 2,00,000 वर्ष पहले एक नई शाख फूटी जिसे मैंने समझाने की कोशिश की है। कि कोई बन्दर इंसान में नहीं बदला। डार्विनिज़्म नहीं कहता कि कोई औरंगोटान नहीं बदला कोई और जानवर 1 दिन में नहीं बदला। बल्कि इसको समझना चाहिए के पेड़ की शाखों की तरह से कोई एक शाख दूसरी शाख में नहीं बदलती, लेकिन एक मोटी शाख में से दूसरी शाख फूट जाती है। यह प्रक्रिया रही है, ये तरीका रहा है जिसमें कुदरत ने इंसान को पैदा किया। धीरे धीरे उसमें बदलाव आया और ये बात अब साबित हो चुकी है के हम जो हैं वे सब अफ्रीका से निकले हैं। यानी सारे इंसान जो हैं वह अफ्रीका से कई लहरों में निकले हैं। आज का इंसान, आज का मानव यानी हमारे पूर्वज उस शाख से निकले हैं जो लगभग 50,000, 55,000 या 45,000 साल पहले अफ्रीका से निकल कर के अरब के जो देश कहलाते हैं, वहाँ से आगे फैलती चली गई। दुनिया में उसकी अलग अलग शाखें हैं। अब सवाल ये है की साइंस किन सवालों के जवाब दे सकती है और किनके नहीं दे सकती? हम ये भी लगातार पूछते हैं कि हम क्यों हैं? तो जब क्यों का मामला आता है तो साइंस उसका जवाब नहीं दे सकती।

प्रश्न - सवाल यह है कि मानव सभ्यता की शरुआत कब हुई, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से मानव सभ्यता का प्रारम्भ होना माना जाता है। इस की वास्तविकता क्या है?

उत्तर - जहाँ तक सभ्यता की शुरुआत का सवाल है तो अब से दस, बारह हज़ार वर्ष पूर्व यह शुरू हुई। उससे पहले तक इंसान जो है वह अंग्रेजी में कहू तो वांटरर, गेदरर यानी वह घूमता है, चीज़े इकट्ठा करता है, बिलकुल जानवरों जैसी ज़िन्दगी है हांला कि इस बीच में ज़बान लगभग 50,000 साल पहले पैदा हो चुकी थी। आपस में बातचीत शुरू हो चुकी थी। मिथ्स हमारे शुरू हो चूके थे। कहानियां हमारी शुरू हो चुकी थीं और ये जो कबीले थे, ये कहानियों के चारों तरफ जैसा कि हरारी कहते हैं, मैं उसको सही मानता हूँ कि मिथ्स के चारो तरफ कबीले इकट्ठा होते हैं। लेकिन ये अभी एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहते हैं। जब खेती की शुरुआत होती है तो मैसोपोटामिया के इलाके में शहरों की शुरुआत होती है। यानी शहर बसने लगते हैं, इंसान जो है वह पहली बार जमीन से बंध जाता है। इससे पहले तक वो जगहजगह घूम कर के खाना इकट्ठा करता है। जहा खतरा बढ़ जाते है वहा से चला जाता है। जहा जंगली जानवरों का ज़्यादा असर होने लगता है, वहा से चला जाता है, पानी कम हो जाता है, खुराक कम हो जाती है तो वह वहा से माइग्रेट कर जाता है। पर अब एक बहुत बड़ा बदलाव यह आता है इंसानी ज़िन्दगी में इंसानी विकास में कि वह जमीन से बंध जाता है। और यहाँ पहली बार प्राइवेट प्रॉपर्टी की धारणा पैदा होती है। यानी यह मेरी ज़मीन है, वे तुम्हारी ज़मीन है, यह मेरा खेत है, यह मेरा घर हैं, यह मेरा परिवार है।

यह बहुत बड़ा बदलाव था इंसानी ज़िंदगी में और यह बात सही है कि अलग अलग इलाकों में जहा ज़मीन उपजाऊ थी और जहा पानी था, और मीठा पानी था खारा पानी नही था और वह पानी सैलाब के यानी फ्लडस के आने से ऊपर तक सीज़नली आता था और वह ज़मीनों को उपजाऊ बना कर जाता था। उसके आसपास सभ्यताओं ने जन्म लिया। हमें मालूम है कि ईजिप्ट मिस्र में जन्म लिया सभ्यताओं ने, मेसोपोटामिया में सबसे पहले शहर पैदा हुए वहा उस इलाके में आबादियो को इतिहासकारों ने एक चाँद की शकल में देखा है। जिस को गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं या फर्टाइल कहते हैं वह उस इलाके में शहर आबाद होने शुरू हुए और इस तरह हमें पता लगता है की सिंधु घाटी जिसे हम सिंध नदी कहते हैं, उसके करीब बहुत सारी सभ्यताएं हैं। बहुत सारे शहर आबाद हुए छोटे, छोटे और यही से इंसानी विकास ने एक नया मोड़ लिया।

प्रश्न - आखरी सवाल आपसे यह है कि एक ज़माने तक चाँद सूरज को देवता ये माने जाता था कि यह भगवान हैं। अब जबकि इंसान चाँद, मंगलग्रह और सूरज पर जाने कि तैयारी कर रहा है तो क्या अब भी इन्हें भगवन माना जायेगा। साइंस इस बारे में क्या कहती है?

उत्तर - जो लोग इन्हें भगवान मानते हैं वह मानते रहेंगे। लेकिन ये बात बहुत साफ है के वही सवाल था के इस ब्राह्मण का जन्म कैसे हुआ?

तो जिन चीजों से फायदा हुआ, जो चीजें अद्‌भुत दिखाई दीं, जिन चीजों के ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं था, उन चीजों के भगवान पैदा हो गए, हिस्टोरियन और साइंटिस्ट यह मानते हैं और साइंस यह मानती है कि पहले जीस तरह से हम कहा करते थे कि सात आसमान हैं और उनमे सब कुछ जड़ा हुआ है और सातवे आसमान के उधर नरक और स्वर्ग है यानी जन्नत और जहन्नुम है और खुदा का घर है। पहले यह मानते थे। अब हमें यह नहीं मालूम कि ऊपर क्या है, और नीचे क्या है? सात आसमान की बात अब कोई कर ही

नहीं सकता क्योंकि आसमान तो है ही नहीं कोई चीज़, यह तोल्मी का मॉडल था जिसकी जड़ें अरस्तु के दौर में मिलती हैं और अरस्तु पहला व्यक्ति है जिसने बहुत साफ तरीके से यह लिखा कि ज़मीन गोल है। और फिर उसने कहा कि सारी चीज़े ज़मीन के चारो तरफ चक्कर लगाती हैं और आसमान है और उस में यह चीज़े चक्कर लगाती हैं। तो जहा तक इन चीजों का देवता होने का सवाल है। मैं समझता हूँ कि अब वो मिथक का ही दर्जा रखते हैं। इससे ज्यादा साइंस में कम से कम उनकी कोई वैल्यू नहीं है।

लेखक : पत्रकार एवं स्तंभकार तथा यू एन एन के संपादक है।

देश विदेश

कनाडा के कैलगरी में बिन क्रिकेट के "कलकत्ता क्रिकेट क्लब

डॉ अशोक श्रीवास्तव

कनाडा में भारतीयों की संख्या का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, हर एक का अनुमान अलग अलग है, कोई कहता है 15 लाख तो कोई 20 लाख, किसी किसी का अंदाज़ा 25-30 लाख तक है.. खैर मेरा तात्पर्य भारतीयों को गिनने का नहीं है. सीधे सीधे यह कहने का है की भाई इतनी बड़ी संख्या अपनी है तो अपने हिन्दुस्तानी खाने के चाहने वालों के लिए भी जगह तो होंगी...और हर जगह होगी.

टोरंटो में तो आपको हर जगह कोई न कोई और विभिन्न तरह के भारतीय खाने के होटल, किचन, बड़े रेस्तरां, कार्नर मिल जायेंगे और नाम भी बहुत ही आकर्षक होते हैं...इसी को ध्यान में रखते हुए सोचा चलो मेरी इस बार के लेखों की श्रंखला में भारतीय भोजन के विभिन्न रेस्तरां का बस परिचय आपसे करवा दिया जाये, ताकि जब आप यहाँ आयें तो आपके पास अपने भोजन को पाने की कुछ न कुछ जानकारी हो और आप परेशान न हों की कनाडा में अपना भोजन मिलेगा या नहीं...

आपको ले कर चलते हैं अल्बर्टा राज्य के शहर कैलगरी के 'कलकत्ता क्रिकेट क्लब' रेस्तरां में, वैसे कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना 1792 में बंगाल में हुई थी लेकिन इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है बस नाम पसंद आया और आकर्षक लगा तो इसके मालिक माया गोहिल नें इसको उसी आकर्षक रूप में ढाल कर बेहतरीन रेस्तरां बना दिया जिसको देख कर लोग ठिठक जाते हैं, जहाँ आपको बंगाल की प्रसिद्ध विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट भोजन की श्रंखला उपलब्ध है और उतरी भारत के साथ कॉन्टिनेंटल भोजन भी उपलब्ध है. रेस्तरां पर लगे क्रिकेट के पुराने धुरंधरों की फोटो आपको बरबस आकर्षित कर लेती हैं और कुछ पुरानी पारिवारिक ब्लैक एंड वाइट फोटो भी अपनी कुछ कहानी कह जाती हैं...

एक बार में करीब 150 लोगों की आवभगत के सक्षम कलकत्ता क्रिकेट क्लब में किसी भी तरह के पारिवारिक, सामाजिक तथा मनोरंजन कार्यक्रम कर सकते हैं हैं...अपनी देशी भाषा में कहूं तो एक यह सही अड्डा है मिलने जुलने का ...

हमने भी पेट भर के भोजन किया और पूरा लुत्फ़ उठाया ..टोरंटो से चार घंटे की फ्लाइट के बाद इतना अच्छा मनभावन खाना मिलेगा उम्मीद कम थी क्योंकि इसके बाद तीन घंटे की ड्राइविंग भी थी...संशय यह भी था की कैलगरी में कोई हिन्दुस्तानी खाना मिलेगा ? तो वो भी दूर हो गया..

आप जब भी कभी कैलगरी आयें तो 'कलकत्ता क्रिकेट क्लब' जायें ज़रूर. हाँ इस बात का ध्यान रखे की लज़ीज़ खाना तो मिलेगा क्रिकेट नहीं

केलगिरी एक बड़ा शहर है जहाँ आबादी काफी है और हवाई अड्डा भी है तो वहां तो ऐसे रेस्तरां मिलना स्वाभाविक था लेकिन केलगिरी से 160 किलोमीटर दूर ज़मीन से 4000 फीट उपर बसे शहर में जिसकी आबादी हमारे एक गाँव से भी कम है लेकिन पर्यटन स्थल गजब का होने के कारण पूरे दिन शहर में भीड़भाड़ लगी रहती है. विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ दिखाई पड़ते हैं बात चल रही है भारतीय भोजन की उपलब्धता पर बैन्फ़ में भी हम तो भारतीय भोजन को तलाश भी नहीं रहे थे क्योंकि उम्मीद कम थी लेकिन घूमते घूमते एक नही. दो नहीं बल्कि तीन तीन रेस्तरां मिले, जिनके नाम थे. ज़ायका, मसाला और इंडियन बिस्तरों..सभी बैन्फ़ अवेन्यु पर...आश्चर्य हुआ...और हमने बिना समय गवाएं जायका जो की पहली मंजिल पर था पहुँच गये...

बड़ा अच्छा लगा देख कर बहुत नही खूबसूरत तरीके से दक्षिण एवं उतरी भारतीय संस्कृति के समावेश से सजाया गया था, अनेक स्थानों पर अनेक भगवानो की तस्वीरें, मूर्ति लगी हुई थी...बुफे खाना लगा हुआ था...वेज, नॉन-वेज दोनों की कई डिशेज लगी हुई थी, सलाद भी कई तरह का, गर्म गुलाब जामुन, आइसक्रीम, रोटियां भी कई तरह की...बस रहा नही गया पहले दाम पूछ लिया की भाई कहीं जेब न खाली हो जाए तो मालूम पड़ा को की मात्र 22 कैनेडियन डॉलर प्रत्येक व्यक्ति..फिर तो हम सब लोग टूट पड़े...भूख जो भयंकर लगी थी...

खाना था बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार. भर पेट खाने के बाद रेस्तरां की कुछ ज़ानकारी ली तो मालूम पड़ा की इसके मालिक हैं श्री अनीश योहन्नान जी जो की केरल से हैं और होटल लाइन का एक बृहद अनुभव रखते हैं..लेकिन जिन्होंने हमारी खातिरदारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करी वो थे मेनेजर साहिब श्री नरेन् कुमार हैदराबाद से...पूरा स्टाफ बहुत ही विनम्र था..

नरेन् ने बताया की अभी दो वर्ष पहले ही यह रेस्तरां ज़ायका शुरू हुआ है और यहाँ पर सुबह दक्षिण भारतीय नाश्ता होता है. दोपहर में मिक्स होता है और डिनर में उतरी भारतीय भोजन चलता है जिसको खाने के लिए भारतीय तो आते ही हैं साथ में सभी देशों के लोग भी बहुत आते हैं...शाम को जगह मिलनी मुश्किल होती है..क्योंकि साथ में बार भी चलता है..

आप यहाँ आयें निश्चिंत हो कर अपने देशी भोजन को छक कर खाएं...

मोदी के शासनकाल में उपेक्षित मीडिया

डॉ. सतीश मिश्रा

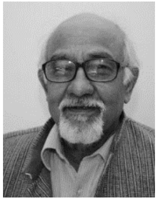

सोमवार, 29 जुलाई 2024 को भारतीय संसद में एक अभूतपूर्व तमाशा देखने को मिला, जब संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा नए नियमों के तहत परिसर में एक कांच के घेरे तक ही सीमित रहने के लिए कहा गया।
संसद के मुख्य प्रवेश द्वार, 'मकर द्वार' की ओर जाने से सुरक्षा गार्डों द्वारा मीडिया को रोके जाने के तुरंत बाद, उस शर्मनाक दिन वहां उपस्थित पत्रकारों ने विरोध स्वरूप किसी भी संसद सदस्य से बातचीत नहीं करने का निर्णय लिया।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष के साथ मिलकर नए नियमों के तहत की गई कार्रवाई को केंद्र द्वारा मीडियाकर्मियों को "पिंजरे में बंद करना" बताया और प्रेस की स्वतंत्रता पर "रोक लगाने" के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा।
लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान गांधी ने स्पीकर बिरला से प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया। कुछ घंटों बाद प्रतिबंध हटा दिए गए, जिसका मतलब साफ था कि मोदी 3.0 सरकार पहली बार झुक गई। यह संसद में मजबूत विपक्ष की मौजूदगी की वजह से ही संभव हो पाया। मोदी 1.0 और मोदी 2.0 सरकारों ने 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के सत्ता में आने से पहले देश में मौजूद जीवंत और स्वतंत्र मीडिया पर सफलतापूर्वक शिकंजा कसा था। जबकि यह घिनौनी घटना 2014 में सत्ता में आई सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की मीडिया नीति का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत "उचित" प्रतिबंधों के साथ गारंटीकृत प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित, विनियमित और नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए कदमों और उपायों की एक बहुत लंबी सूची है।

इतना ही नहीं, मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से प्रेस की स्वतंत्रता पर भारत की रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) द्वारा जारी 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट में भारत 159वें स्थान पर है, जो विडंबनापूर्ण है कि 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से दो पायदान ऊपर है। आरएसएफ ने दो रैंक में सुधार को "भ्रामक" करार दिया क्योंकि उसने कहा कि वास्तव में स्कोर में गिरावट आई है, लेकिन स्थिति में यह परिवर्तन पहले से ऊपर के देशों की बदतर गिरावट के कारण हुआ है।
आरएसएफ ने डेटा जारी करते हुए कहा, "पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, अत्यधिक केंद्रित मीडिया स्वामित्व, राजनीतिक गठबंधन के कारण 'दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र' में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है, जिस पर 2014 से भाजपा के नेता और हिंदू राष्ट्रवादी दक्षिणपंथ के अवतार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन है।"

29 जुलाई 2024 को संसद में एक अद्वितीय घटना देखने को मिली, जब मीडियाकर्मियों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नए नियमों के तहत कांच के घेरे में सीमित कर दिया गया। इस घटना ने प्रेस की स्वतंत्रता पर गहरे सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को "मीडिया को पिंजरे में बंद करना" करार दिया

भारत पर अपनी रिपोर्ट में आरएसएफ ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति कई मामलों में खराब हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के दिग्गज मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री के निजी मित्र हैं और उनके पास 70 से अधिक मीडिया आउटलेट हैं, जिन्हें कम से कम 800 मिलियन भारतीय फॉलो करते हैं। 2022 के अंत में गौतम अडानी द्वारा NDTV चैनल का अधिग्रहण, जो मोदी के करीबी भी हैं, मुख्यधारा के मीडिया में बहुलवाद के अंत को चिह्नित करता है। हाल के वर्षों में "गोदी मीडिया" (मोदी के कुत्तों को नामित करने के लिए व्यंग्य) का उदय भी देखा गया है - मीडिया आउटलेट जो लोकलुभावनवाद और भाजपा समर्थक प्रचार को मिलाते हैं। दबाव और प्रभाव के माध्यम से, बहुलवादी प्रेस के पुराने भारतीय मॉडल पर सवाल उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री पत्रकारों की बहुत आलोचना करते हैं, उन्हें अपने समर्थकों के साथ अपने सीधे संबंधों को दूषित करने वाले "मध्यस्थ" के रूप में देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय पत्रकार जो सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, उन्हें भाजपा समर्थित ट्रोल द्वारा उत्पीड़न अभियानों का शिकार होना पड़ता है।
2019 में, वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार से मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के भी बिना पूर्व नियुक्ति या अनुमोदन के मंत्रालय के परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, जिससे फिर से एक बहस छिड़ गई है, जिससे यह चिंता पैदा हो गई है कि क्या देश की संचार प्रणाली धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से सूचना के मुक्त प्रवाह से प्रतिबंधित, विनियमित और नियंत्रित शासन की ओर बढ़ रही है।

यद्यपि यह मोदी सरकार के दूसरे चरण में उठाया गया पहला कदम था, लेकिन यदि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और आरएसएस-भाजपा के बीच 25 वर्षों से अधिक के संबंधों पर करीब से नजर डालें तो यह न तो पहला था और न ही अंतिम।
हालांकि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस एसोसिएशन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और इंडियन वूमेन प्रेस कॉर्प्स तथा फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब जैसे पेशेवर मीडिया संगठनों ने इस निर्णय पर विरोध दर्ज कराया है तथा सरकार से नवीनतम प्रतिबंध को वापस लेने को कहा है, लेकिन मोदी सरकार ने विरोध को नजरअंदाज कर दिया तथा अपने उसी रास्ते पर अड़ी रही, जिससे समाचार एकत्र करना एक असंभव कार्य बन गया।

सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के माध्यम से न्यूनतम पांच वर्ष के अनुभव वाले पत्रकारों को मान्यता देती है। गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत सुरक्षा जांच के बाद दी जाने वाली मान्यता "सरकार में सूचना और समाचार सामग्री तक पहुंच" के लिए है... एक पत्रकार का प्राथमिक कर्तव्य सरकार के सभी स्तरों और परतों से ऑन

और ऑफ रिकॉर्ड दोनों तरह से जुड़ना है ताकि वह जानने के अधिकार के आधार पर लोगों को सूचित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा कर सके।

मीडियाकर्मियों को उनके समाचार संकलन कार्यों के लिए अपेक्षाकृत अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान करना सरकार द्वारा दिया गया कोई उपकार या उपहार नहीं है और इसे तत्कालीन सरकार की मर्जी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल या उससे पहले गुजरात में उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मीडिया को सूचना तक पहुँच से रोकने, सीमित करने और मना करने का एक स्पष्ट पैटर्न देखने को मिला। मई 2014 में केंद्र और भाजपा शासित राज्यों में सत्ता संभालने के तुरंत बाद, यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। मोदी के राष्ट्रीय परिदृश्य पर आने के बाद भाजपा में भी इसी तरह के घटनाक्रम देखने को मिले। जब तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उनके सहयोगी अमित शाह को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया तो पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों तक मीडिया की पहुंच सीमित कर दी गई। यह उस अप्रतिबंधित पहुंच से बिल्कुल अलग था जो पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को तब मिलती थी जब पार्टी अपनी छवि बदलने के लिए मीडिया का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी।

जुलाई 1915 में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त महानिदेशक (मीडिया) को मीडिया को सभी प्रचार सामग्री के "एकल बिंदु प्रसार" के रूप में नामित करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें इसके द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण भी शामिल थे। दिशा-निर्देशों में इस बात पर भी जोर दिया गया कि मीडिया को सूचना जारी करना केवल केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी से ही किया जाएगा। साथ ही, इन निर्देशों में मंत्रालय में पत्रकारों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। इसमें कहा गया है, "मीडियाकर्मियों को सूचना देने के लिए मीडिया कक्ष संख्या 9 में व्यवस्था की जाएगी। मीडियाकर्मियों से एडीजी (मीडिया) द्वारा कहा जाएगा कि वे मीडिया कक्ष के अलावा अन्य किसी अधिकारी से मुलाकात न करें।"

सुरक्षा परिदृश्य की ओर इशारा करते हुए रक्षा मंत्रालय ने भी साउथ ब्लॉक में अधिकारियों और सेवा कर्मियों को मीडिया से सीधे बात न करने की चेतावनी देते हुए एक सर्कुलर जारी किया था, जबकि उनसे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से संवाद करने के लिए कहा गया था। इसी तरह के प्रतिबंध या तो पहले ही लागू किए जा चुके हैं या अन्य मंत्रालयों में लागू किए जाने की प्रक्रिया में हैं। मीडिया के कार्य को कठिन बनाना तथा सरकारी चैनलों तक पहुंच से वंचित करना, नई दिल्ली में प्रेस कोर के मान्यता प्राप्त तथा गैर-मान्यता प्राप्त सदस्यों को आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन गांधीनगर तथा अहमदाबाद के मित्रों को नहीं, जहां 2001 से 2014 के बीच पत्रकारों का जीवन चुनौतीपूर्ण तथा कठिन हो गया था, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे।

सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करना और उस पर प्रतिबंध लगाना गांधीनगर में मोदी की शासन शैली की खासियत थी। सचिवालय में पत्रकारों की पहुंच धीरे-धीरे सीमित कर दी गई। बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री द्वारा सचिवालय को नियमित रूप से कवर करने वाले

> *मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मीडिया की स्वतंत्रता लगातार गिरती जा रही है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159 वां रहा, जो सरकार की प्रेस नीति पर गंभीर सवाल खड़े करता है।*

मीडियाकर्मियों को अपने कक्ष में ब्रीफ करने की लंबे समय से चली आ रही और चली आ रही प्रथा धीरे-धीरे खत्म हो गई।

मुक्त आवागमन और बातचीत से मीडियाकर्मियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया की पेचीदगियों की समझ मिलती है, क्योंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी अनौपचारिक रूप से उन्हें चीजें समझाते हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले कार्यों में से एक के रूप में, प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्राओं पर गैर-सरकारी मीडियाकर्मियों को अपने साथ ले जाने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा को समाप्त कर दिया और इस प्रकार सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित किया, क्योंकि दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार एजेंसियों जैसे आधिकारिक मीडिया को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन करना आसान है।

कोविड-19 के नाम पर संसद के दोनों सदनों में पत्रकारों की पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई थी, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद भी इसे बहाल नहीं किया गया।

यहां यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न सरकारों ने, जिनमें भाजपा और कांग्रेस दोनों शामिल हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकारों की पहुंच को सीमित कर दिया है। मुझे याद है कि एक बार प्रेस सूचना ब्यूरो कार्ड के साथ मैं विदेश मंत्रालय या दक्षिण बोक में पीएमओ में अधिकारियों से मिलने जा सकता था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया और फिर मैं दोनों में से किसी में भी प्रवेश नहीं कर सका।

लोकतंत्र में हर सत्तारूढ़ पार्टी मीडिया से आशंकित, सतर्क, चिंतित और कभी-कभी भयभीत रहती है। विपक्ष में, सभी दल स्वतंत्र मीडिया के गुणगान गाते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि जब भूमिका उलट जाती है तो वे गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं।

2024 तक स्थिति बिलकुल अलग थी, जब विपक्ष बंटा हुआ और कमजोर था। सरकार को किसी भी तरफ से कोई खतरा नहीं था। मोदी का लोगों से सीधा जुड़ाव था। आम चुनावों में अविश्वसनीय जीत के बाद लोकप्रिय लहर पर सवार होकर और मीडिया के बारे में संदेह और संदेह का माहौल बनाने में सफल होने के बाद, मोदी सरकार को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि सत्तारूढ़ दल को यकीन था कि व्यापक जन आंदोलन की संभावना या तो दूर की बात है या फिर है ही नहीं।

2024 के आम चुनावों में लोकप्रिय जनादेश विपक्ष को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होगा और यह देखना बाकी है कि मोदी, जो स्वेच्छा से किसी भी विरोध या असहमति को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लोगों तक सूचना पहुंचाने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मीडियाकर्मियों पर प्रतिबंधों में ढील कैसे देते हैं।

स्वतंत्र मीडिया के कामकाज के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने की लड़ाई लंबी और जोखिम भरी है। उम्मीद इस बात पर टिकी है कि विपक्षी दल भारत ब्लॉक और एनडीए का समर्थन करने वाली कुछ पार्टियाँ जैसे टीडीपी और जेडी (यू) मीडिया यूनियनों और संगठनों के साथ मिलकर पिछले दशक में जो खो गया है उसे वापस पाने के लिए कैसे संघर्ष करती हैं।

लेखक : वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक एवं मीडिया मैप के संयुक्त संपादक हैं।

“कोविड-19 के समय आर्थिक तंगी में धकेले गये पत्रकार”

मीडिया मैप न्यूज़

कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में और उसके बाद के दौर में अखबारों और मीडिया संगठनों द्वारा की गई बड़े पैमाने पर छंटनी ने देश भर में 2,500 से ज़्यादा पत्रकारों को बेरोज़गार कर दिया। इनमें से ज़्यादातर पत्रकारों को धमकाया गया, उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया गया और बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे वे दरिद्रता, लाचारी और लंबे समय तक अवसाद में डूबे रहे।

कोविड-19 महामारी के दौरान पत्रकारों की छंटनी पर इस सप्ताह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में ये परेशान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। कोविड-19 अवधि के दौरान मीडिया समूहों द्वारा पत्रकारों की छंटनी पर रिपोर्ट शीर्षक वाली यह रिपोर्ट महामारी के दौरान पत्रकारों की छंटनी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सितंबर 2023 में गठित पीसीआई की एक उप-समिति द्वारा तैयार की गई थी। पीसीआई ने पहले मीडिया उद्योग में बड़े पैमाने पर नौकरियों के नुकसान का स्वतः संज्ञान लिया था। 22 पन्नों की यह रिपोर्ट अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगाली भाषाओं के 17 समाचार संगठनों और 12 पत्रकार यूनियनों और एसोसिएशनों के कुल 51 पत्रकारों के बयानों के आधार पर तैयार की गई थी।

उप-समिति द्वारा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के प्रेस क्लबों में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान गवाहियाँ एकत्र की गईं। समिति के समक्ष गवाही देने वालों में नई दिल्ली और मुंबई स्थित अंग्रेजी भाषा के समाचार मीडिया के पत्रकारों की संख्या सबसे अधिक है।

रिपोर्ट के अनुसार, महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले 80% पत्रकारों को इस्तीफा देने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनके समाचार संगठनों ने उन्हें अपने पदों से बर्खास्त कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें से अधिकांश पत्रकारों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया या बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू में पूर्व पीसीआई सदस्य बलविंदर सिंह और स्वतंत्र पत्रकार सिरिल सैम द्वारा किए गए स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार छंटनी लगभग 2,300 से 2,500 के बीच हुई है। हालांकि, वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक होने की संभावना है क्योंकि उनका डेटा मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा के मीडिया तक ही सीमित है। गवाही देने वालों में से लगभग 80% तीन प्रमुख प्रकाशकों से थे - 19 बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड से, 14 एचटी मीडिया से और 8 द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप से। समिति के समक्ष गवाही देने वालों में नई दिल्ली और मुंबई स्थित अंग्रेजी भाषा के समाचार मीडिया के पत्रकार सबसे अधिक थे। भौतिक बयानों और ऑनलाइन प्रस्तुतियों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट को पीसीआई ने 5 अगस्त को अपनाया था। उप-समिति 2023 में गुरबीर सिंह, प्रजनंद चौधरी, पी. साईनाथ, स्नेहाशीष सूर, एलसी गुप्ता और सिरिल सैम शामिल थे।

> ***कोविड-19 महामारी के दौरान देशभर के 2,500 से अधिक पत्रकारों को बिना किसी उचित प्रक्रिया के नौकरी से निकाल दिया गया। इनमें से अधिकांश पत्रकारों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट और मानसिक अवसाद का सामना कर रहे हैं।***

समिति के समक्ष गवाही देने वाले केवल 25% पत्रकारों ने कहा कि उन्हें छंटनी के बारे में उनकी कंपनियों से औपचारिक ईमेल प्राप्त हुए हैं। लगभग 75% मामलों में, छंटनी के बारे में सभी संचार मौखिक थे। भौतिक सुनवाई में, 80% पत्रकारों ने दावा किया कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था और उन्हें वेतन कटौती और छंटनी के बारे में कोई अग्रिम सूचना या औपचारिक संचार नहीं मिला।

कविता अय्यर, जो वर्तमान में एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम कर रही हैं, को प्रकाशन में 18 साल बिताने के बाद 27 जुलाई, 2020 को इंडियन एक्सप्रेस के मुंबई ब्यूरो से निकाल दिया गया। रिपोर्ट में उनके सहकर्मियों को भेजे गए एक ईमेल का हवाला दिया गया है जिसे 2020 में अय्यर की अनुमति से प्रकाशित किया गया था। अय्यर ने कहा कि उन्हें एक बैठक में सूचित किया गया था - जिसमें उन्हें अपना फोन बाहर छोड़ने के लिए कहा गया था - कि उन्हें इस्तीफा देना होगा और रिलीविंग लेटर स्वीकार करना होगा या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा।

द हिंदू अख़बार के पूर्व मार्केट एडिटर आशीष रुखैयार को 19 जून, 2020 को उनके पद से हटा दिया गया। 3 अगस्त, 2020 को समाचार संगठनों को लिखे एक खुले पत्र में उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा: "रिपोर्टरों को फ़ोन पर नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ को दफ़्तर बुलाया गया और तुरंत इस्तीफ़ा देने को कहा गया। नौकरी से निकाले जाने की ख़बर नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई। उन्हें धमकी दी गई कि अगर वे इस्तीफ़ा नहीं देंगे, तो वे कानून के तहत मिलने वाले भुगतान से वंचित हो जाएँगे। इस पागलपन में कोई तरीका नहीं था। कोई मेमो नहीं, कोई प्रदर्शन-संबंधी चेतावनी नहीं, मूल्यांकन में कोई लाल झंडी नहीं, आदि।"

सुनीता तिवारी, जो 20 से ज़्यादा सालों से हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़ी हुई थीं, को 30 अगस्त, 2020 को प्रकाशन से जुड़ी बच्चों की पत्रिका 'नंदन' से इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया। कथित तौर पर उसी महीने पत्रिका बंद कर दी गई। तिवारी ने समिति के सामने गवाही दी कि इस्तीफ़ा देने के लिए कहे जाने के बाद, उनकी मधुमेह की बीमारी बढ़ गई और बाद में, उन्हें अवसाद का पता चला। तिवारी ने यह भी गवाही दी कि उनके एक सहकर्मी संतोष गुप्ता, जो संगठन में डिजाइनर थे, की छंटनी के बाद आत्महत्या कर ली गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति के समक्ष गवाही देने वाले अधिकांश पत्रकारों ने महसूस किया कि उनके काम के लिए उन पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन एक्सप्रेस ने 11 जुलाई, 2020 से 30 जुलाई, 2020 के बीच विभिन्न क्षेत्रों और प्रकाशनों में कम से कम 35 से 40 पत्रकारों की छंटनी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के दौरान अपनी नौकरी खोने वाले पत्रकार गंभीर वित्तीय संकट में फंस गए, जबकि संगठन उन्हें मुआवज़ा देने के लिए तैयार नहीं थे।

गौरतलब है कि इनमें से कई पत्रकार, खास तौर पर रिपोर्टर और फोटोग्राफर, महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान खतरनाक परिस्थितियों में ज़मीन पर काम कर रहे थे और उन्होंने पीपीई किट, मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च किए थे। समिति के समक्ष गवाही देने वाले पत्रकारों में से केवल 37% को ही उनके अनुबंध के अनुसार विच्छेद वेतन मिला है।

मुंबई मिरर के फोटोग्राफर दीपक तुरभेकर को जनवरी 2021 में संगठन ने व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए इस्तीफ़ा देने के लिए कहा था। संगठन ने 5 दिसंबर, 2020 को अपने दैनिक प्रिंट संस्करण का प्रकाशन बंद करने का फ़ैसला किया था। संगठन के साथ 16 साल से ज़्यादा समय बिताने वाले तुरभेकर को धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उनकी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और दूसरे लाभ रोक दिए जाएँगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्भेकर अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के बारे में बताते हुए समिति के सामने रो पड़े। वे तीन साल से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कंपनी ने उनके इस्तीफे पर उन्हें सिर्फ़ एक महीने का वेतन दिया। उन्होंने मुंबई में अपने घर का लोन चुकाने के लिए पीएफ के पैसे का इस्तेमाल किया और बंधक के लिए अपना बीमा सरेंडर कर दिया।

तुर्भेकर ने बताया कि उन्हें अपनी बड़ी बेटी की शिक्षा के लिए अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े। उनका एक छोटा बेटा तीसरी कक्षा में पढ़ता है। "मेरे पास फोटोग्राफी के लिए उपकरण खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और अब मैं समाचार फोटोग्राफी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह टिकाऊ नहीं है। फ्रीलांस न्यूज़ फ़ोटोग्राफ़रों को प्रति फ़ोटो केवल 100 से 150 रुपये के बीच भुगतान किया जाता है। मुझे भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं दिखती," उन्होंने कहा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्भेकर जैसे कई लोगों ने आर्थिक तंगी के कारण पत्रकारिता छोड़ने का फैसला किया है। उनमें से एक प्रशांत नकवे थे, जो मुंबई के द हिंदू के पूर्व फोटो संपादक थे, जिन्हें 22 जून, 2020 को एक ईमेल के ज़रिए संगठन से निकाल दिया गया था। उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी है और अब अपनी पत्नी के घर में पका हुआ खाना और टिफ़िन का व्यवसाय शुरू करने में उनकी मदद कर रहे हैं, जिसे नकवे की छंटनी के बाद शुरू करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा।

नकवे ने समिति को बताया, "महामारी के दौरान हमसे रोज़ाना तस्वीरें दर्ज करने की अपेक्षा की जाती थी और हमें कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए या सुरक्षा उपकरणों के लिए किए गए जेब से किए गए खर्च के लिए मुआवज़ा नहीं दिया गया। अब कैमरे की तुलना में रसोई का चाकू मेरे हाथ में ज़्यादा रहता है।" रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर वित्तीय स्थिति के साथ-साथ, आजीविका के अचानक नुकसान ने भी इन पत्रकारों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला है। रिपोर्ट में कहा गया है, "छंटनी ने समिति के

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया संगठनों ने महामारी के दौरान पत्रकारों को आवश्यक कर्मचारी मानने के सरकारी निर्देश की अनदेखी की और बड़े पैमाने पर छंटनी कर दी। यह कदम पत्रकारों की आजीविका और प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है।

समक्ष उपस्थित होने वाले 40 (80%) पत्रकारों को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। छंटनी ने 40 (80%) पत्रकारों के आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को भी प्रभावित किया। 30 (60%) पत्रकारों ने अवसाद की शिकायत की और 27 (54%) ने सामाजिक अलगाव का अनुभव किया। विशेष रूप से वरिष्ठ पत्रकार भावनात्मक रूप से सबसे अधिक प्रभावित हुए। यह शारीरिक सुनवाई में भी देखा गया, जहां कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भावनात्मक उथल-पुथल का अनुभव किया और वे रो पड़े।"

रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकारों के लिए स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि समाचार मीडिया संगठनों ने महामारी के दौरान मीडिया पेशेवरों को आवश्यक कर्मचारी के रूप में सूचीबद्ध करने के केंद्र सरकार के निर्देश पर विचार करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है, "समाचार मीडिया को आवश्यक कर्मचारियों की श्रेणी में शामिल करने का कारण यह मान्यता थी कि संकट के समय में समाचार और सूचना का प्रसार विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जब लोग दैनिक आधार पर बदलती महामारी की स्थिति से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जब सूचना के अनौपचारिक चैनलों में अफ़वाहें लोगों की समझ को धुंधला कर रही हैं। हालाँकि, हमें यह दर्ज करना होगा कि अधिकांश मीडिया कंपनियों ने आवश्यक कर्मचारियों के इस निर्देश को नज़रअंदाज़ किया, और उन्होंने केंद्र सरकार के निर्देश के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया, पत्रकारों को अपनी मर्जी से नौकरी से निकाल दिया और उनकी छंटनी कर दी।"

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सरकार ने अपने निर्देश को अमल में लाने के लिए बहुत कम प्रयास किया।

रिपोर्ट में कहा गया है, "जब मुंबई और महाराष्ट्र के पत्रकारों ने राज्य सरकार से अपील की कि उन्हें आवश्यक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मीडियाकर्मियों को बिना किसी बाधा के लोकल ट्रेनों और परिवहन का उपयोग करने की अनुमति दी जाए, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मांग को खारिज कर दिया। पत्रकारों के प्रतिनिधियों ने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से हस्तक्षेप करने और कंपनियों द्वारा मीडियाकर्मियों को बड़े पैमाने पर नौकरी से निकालने से रोकने का अनुरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।" रिपोर्ट में कहा गया है, "अगर पत्रकारों को नौकरी की सुरक्षा नहीं मिलती है, तो उस समय प्रेस की स्वतंत्रता से समझौता होता है।" रिपोर्ट में पत्रकारों के काम करने के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सिफारिशें भी शामिल की गई हैं। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि नौकरी की सुरक्षा के संबंध में मीडिया पेशेवरों के सामने आने वाले मुद्दों के केंद्र में मौजूदा अनुबंध प्रणाली और रोजगार की आकस्मिक प्रणाली है, रिपोर्ट में सूचना और प्रसारण मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय से कुछ अनिवार्य धाराओं के साथ एक मॉडल अनुबंध बनाने का आग्रह किया गया है।

इन प्रावधानों में 7 से 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि, लागू मामलों में पीएफ, ग्रेच्युटी, कर्मचारी राज्य बीमा देने का प्रावधान, छुट्टी का प्रावधान, वेतन में वार्षिक वृद्धि आदि शामिल हैं। रिपोर्ट में सेवा समाप्ति के मामले में न्यूनतम छह महीने के वेतन के बराबर विच्छेद भुगतान की भी सिफारिश की गई है

सितम्बर 14 : हिंदी दिवस

हिंदी के साथ अंतरराष्ट्रीय खिलवाड़

अनूप श्रीवास्तव

खेल खेलना बुरा नहीं हैअगर वह घर मे या मैदान में खेला जाए। गड़बड़ी तब आती है जब उसे गली से निकल कर सड़क पर खेला जाने लगता है। वैसे भी खेल के साथ खेलना किसी के भी गले नहीं उतरता। हम माता को विमाता के गले मढ़ने में हिचकते हैं पर इससे भी भद्दा खिलवाड़ हम हिंदी के साथ कर रहे हैंऔर हिंदी को ग्लोबल बनाने के नाम पर यह काम धड़ल्ले से किया जा रहा है।

गम्भीर और दुख की बात यह है कि यह काम हम अनजाने ही नहीं बल्कि जानबूझकर धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसे भाषा के साथ एक अंतरराष्ट्रीय खिलवाड़ भी कह सकते हैं ।

वैसे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम खेल खेले जा रहे हैं जैसे सुरक्षा का खेल, आतंकवादकाखेल,उत्पादवाद-बाज़ारवाद का खेल और दादागिरी का खेल । नस्लवाद वंशवाद से होती हुई दादागिरी भाषा के साथ अपनी गोटियां फिट करने में लगी है । इसलिए भाषा की परिभाषा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गढ़ी जा रही है । हिंदी के पाले में हम बड़ी हनक के साथ अंग्रेजी में गिटिर- पिटिर करते हैं पर माइक और मंच देखते ही हिंदी वाले हो जाते हैं उनके सत प्रयासों से भाषा अब एक मोहरा भर है क्योंकि वे जानते हैं कि हिंदुस्तान के बाजारों में हिंदी की बेल मढ़े बगैर पैर रख पाना मुश्किल है । साज़िश यह है कि हिंदी को घुन लग जाए ताकि हिंदी के नाम पर उसी की प्रजाति को स्थापित किया जा सके। फैलाया जा सके।

आखिर हो क्या रहा है ? हिंदी बोलने वाले, पढ़ने वालेऔर लिखने वाले बढ़ रहे हैं।।लेकिन उसके तथाकथित विकास की दादागिरी में प्रभुत्व उनका होने जा रहा है जो भाषा की सम्वेदना से अनभिज्ञ हैं । हिंदी की काकटेल तैयार करने की तैयारिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोरों से की जा रही है । अमरीकी साम्राज्यवाद की नज़र उसी काकटेल पर लगी हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन इसकी एक प्रयोशाला भर कही जा सकती है । न्यूयार्क का आठवां इससे परे नहीं थाऔर मारिशश में होने वाला ग्यारहवां अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन भी उसी प्रस्तावना की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है ।

सूरीनाम में जब सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो दिवंगत कमलेश्वर जैसा लेखक वहां के अपमान,अव्यवस्था

और अराजकता से व्यथित होकर होटल की सीढ़ियों पर रो पड़े थे । लौट कर कमलेश्वर जी ने यह बात कही भी थी कि भाषा के साथ हो रहे इस कुचक्र को रोकना तो दूर स्वयम को महिमा मंडित समझ कर आंख मूंदे हुए हैं ।

महत्व पूर्ण बात यह है कि हिंदी के प्रति अचानक यह प्रेम क्यों उमड़ रहा है ? क्या इसलिए कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में हिंदी बाज़ार की भाषा के साथ मीडिया की ताकतवर भाषा भी बन रही है ।

विज्ञापन और सीरियल की भाषा बनकर ड्राइंगरूम और स्टडी तक पहुंच रही है और अब हिंदुत्व की लहर भी हिंदी के नाव को अमरीकी चैनल में तेजी से खे रही है। इसी के साथ ही हिंदी का वाक्य विन्यास भी अंग्रेज़ी के साथ ढल रहा है ।

इधर आधुनिकता की गंध और 'आई टी' का रस भी घुलने लगा है। विदेशी पैसों की धमकी पर अखबारों की भाषा भी बदलने लगी है जिसके ताज़ा नमूने हिंगलिश के नए अखबार हैं जो हिंदी को रोमन लिपि देने की पूर्व पीठिका माने जा सकते हैं । लेकिन इस ओर सोचने की हमे फुर्सत ही नही है और यह जानकर भी हम जानना नहीं चाहते कि हिंदी जितनी ग्लोबल होगी उतनी ही फूहड़ और विद्रूप होती जाएगी।

हिंदी की माथे की बिंदिया कहीं उखड़ न जाये इस हद तक

हास्य व्यंग क्षणिकाएँ

सत्ता की दलाली

चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष,

सत्ता की दलाली में,

दोनों ही है- उभय पक्ष !

इसका मतलब,

पूरी तरह से साफ है।

सत्ता दरअसल में,

सिर्फ दो मुहाँ साँप है।

एक नागनाथ,

तो दूसरा सापनाथ है,

और सत्ता की,

पारसमणि झटके बिना,

दोनों ही अनाथ हैं।

भ्रष्टाचार की बांबी में,

पाते दोनों ही पनाह है।

सबकी अलग-अलग

भूमिका है- एक करता

वाह! वाह !! है, तो

दूसरा आह! आह है !!

ये जो ज़हर नफ़रत का

प्रदूषण का हवीओं में

तू फैला रहा है

उसका असर तेरे

परिवार और पूरे देश को

खा रहा है.

– डा. रवीन्द्र कुमार

हास्य व्यंग

हिंदी भाषा का कटोरा !

अनूप श्रीवास्तव

भाषा के नाम पर कटोरा हाथ में लेने का समय फिर आ गया। जिसके पास जितना बड़ा कटोरा होता है वह उतना ही बड़ा आदमी माना जाता है। जिस हालात में आम आदमी उल्टा कटोरा लिए खड़ा है वहाँ सिर्फ सीधा कटोरा लेने वाले की ही पूजा होती है।

भीख मांगने के लिए कुछ न कुछ आधार बनाना ही पड़ता है ।भगवान के नाम पर, जनहित के नाम पर तो कभी विकास के नाम पर। कुछ भी न सुझाई पड़े तो साल में कुछ दिन भाषा के नाम पर हम साल भर पूरी दुनिया के सामने कटोरा लिए खड़े रहते हैं। ऐसे में अगर भाषा के नाम पर हम आपके सामने हैं तो इसमें बुरा क्या है। भाषा का उद्धार करना,उसको सर्वव्यापी बनाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।

चीन,फ्रांस,अमेरिका,इंग्लैंड,रूस जैसे देश अपनी अपनी भाषा में व्यस्त रहते हैं। कूप मण्डूक हैं ये सारे देश ।एक हम हैं जो त्याग और तपस्या के स्वयम्भू अवतार हैं। हम अपनी भाषा के मुकाबले औरों की भाषा को सम्बल देते हैं। साल भर अंग्रेजी की उंगली पकड़ कर सीना फुलाये घूमते रहते हैं। तमाम भाषाओं के ट्यूशन क्लासेस चलाते रहते हैं। पद की शपथ भी अंग्रेजी में लेने में फक्र महसूस करते हैं। अगर ऐसे में अगर मात्र साल के आधे महीने भर हम हिंदी के रियल्टी शो (जो रियल नही हो पाता) का दिखावा करते हैं तो क्या बुरा करते हैं।

कहते हैं हिंदी भाषा एक विचार है। इस विचार को हमने बिचारी बनाकर रख दिया है। सितम्बर में एक बार फिर उस विचार पर बकबक करने का समय आ गया है। हिंदी संस्थानों ,रेलवे स्टेशनों, सरकारी प्रचार पटों और तमाम अनुवादित सरकारी सूक्तियों में हम पढ़ते आये हैं हिंदी से सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। यह काम हम खासतौर से एक पखवारे तक पूरी शिद्दत से करते हैं। बाकी साढ़े ग्यारह महीनों में हम भारत को कई सूत्रों में पिरोते रहते हैं। जैसे त्योहारों में हम पूरे देश को भाईचारे के सूत्र में, राष्ट्रीय पर्वों पर अखण्डता और एकता के सूत्र में ,चुनाव के समय विकास और खुशियाली के सूत्र में बांधे रहते हैं वैसे ही 14 सितम्बर से मात्र एक पखवारे तक हिंदी को पूरे देश को बांधे रखने का संकल्प दुहरा लेते हैं । इसमें हमारी कभी जुबान तक नहीं थकती।

तो आइए भाषा के नाम पर हम एक बार फिर अपने राष्ट्र भाषा के मुद्दे पर कटोरा लेकर निकलें और चीख चीख कर कहें कि हिंदी हमारी मातृभाषा है।खुलकर कहें कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है।खुलकर कहें कि हिंदी हमारी पहचान है।

बिना घबराहट के कहें-हिंदी हमारी अस्मिता है। जल्दी कीजिये।हिंदी के नाम पर,हिंदी की झोली में कुछ हिंदी जैसा डाल दीजिए। आखिर साल भर में हम एक बार ही तो अपनी बोली,अपनी भाषा के लिए थोड़ा सा समय निकाल पाते हैं।इसपर नज़र न लगाइए। क्या मातृभाषा के नाम पर हम थैंक यू की जगह धन्यवाद नहीँ बोल सकते? मात्र एक पखवारे तक के लिए ही। मात्र एक शब्द हिंदी के कटोरे में आजादी के 75 वर्ष की स्वर्णजयंती पर भी हम हिंदी को राष्ट्र भाषा का दर्जा देने की मांग तक नही दुहरा रहे हैं । आपके हिंदी में किये गए हस्ताक्षर को भी हम मान देते हैंऔर इतने में ही हिंदी डे मना लेते हैं।कहना हो तो जल्दी कहिए।करना हो तो जल्दी करिये। कहीं ऐसा न हो कि हिंदी के नाम पर कुछ कहने

सुनने के लिए इस साल भी "हिंदी पखवारा" निकल जाए एवं हिंदी अपनी खाली झोली लेकर अगले सितम्बर के लिए आगे बढ़ जाये। और हम एक बार फिर " भाषा का कटोरा हिंदी की बैसाखी लगाने से चूक जाएं।

क्षणिका

हिंदी पखवाड़ा !

हिंदी पखवाड़ा,मनाने की ,चख चख के
दौरान, मैंने कहा बड़े बाबू !आप साल भर
तो , सारा कामकाज -अंग्रेजी मे निपटाते
हैं, लेकिन हफ्ता पन्द्रह दिनों के लिए
,अचानक एकदम बदल जाते हैं, और सिर्फ
हिंदी हिंदी चिल्लाते हैं .
सचमें बतालाइए बड़े बाबू ! आपको
आफिस की कसम,इस बार भी आपको
क्या , हिंदी पखवाड़ा मनाने काख्याल
अचानक ही आया है ?बड़े बाबू फुसफुसा
कर बोले -शोर मत मचाइये, बोलिये
लेकिन होले- होले,
मैंने फिर दोहराया - लेकिन आपको कैसे
पता चला ?
ऐसे क्योंकि --
पिछले साल की तरह
हमारा बास कुर्सी पर बैठते ही हिंदी में हिंदी
में फिर मुस्कुराया है .
इसीलिए साहेब के आदेश पर पूरे पखवाड़े
भर दफ्तर में अब हिंदी सप्ताह मनाया
जाएगा मुख्य द्वार पर वेलकम का बैनर इस
बार भी लगाया जाएगा और फंक्शन का
चीफ गेस्ट बांकायदा टेंडर निकालकर
किसी हिंदी पंडित को बनाया जाएगा .

इस दौरान हिंदी में, हम जो भी लिखे पढ़ेंगे.
ऑफिस में किये गए हमारे, हस्ताक्षर तक
फाइल में चढ़ेंगे. हिंदी में की गई टिप्पणी को
हम, फिल्मी अंताक्षरी की तरह दिखाएंगे ,
सभी साथियों को बाद में, हल्का-फुल्का
पुरुस्कार भी, साहेब के हाथों थमाया
जाएगा.

मैंने फिर सवाल किया - लेकिन 'श्राद्ध पक्ष'
के दौरान ही आप 'हिंदी सप्ताह' क्यों मनाते
हैं वे बुरा मानते हुए बोले -- तुम हिंदी वालों
की , यही तो बुरी आदत है . बैठे ठाले ही
हर जगह ,
अपनी टांग अड़ाते हो.

यह भी कोई बात हुई , अरे! हम सरकारी
आदमी हैं , इसलिए घर में दफ्तर का काम,
और दफ्तर में घर का काम ,
घर ले जाकर निपटाते हैं.

चाहे श्राद्ध हो या श्रद्धा, दोनों में ही हमारी
श्रद्धा है . इसीलिए यह दोनों ही, आपको
एक साथ , तभी नजर आते हैं .
जब हम साहेब के आदेश से. हिंदी
पखवाड़ा मनाते हैं !

-अनूप श्रीवास्तव

मीडिया मैप वेबसाइट पर

शिक्षा, विकास और नास्तिकता का परस्पर संबंध

शैलेन्द्र चौहान

धर्म के प्रति मुख्य आकर्षण का एक कारण यह है कि यह अनिश्चित दुनिया में सुरक्षा का काल्पनिक अहसास दिलाता है. लेकिन बावजूद इसके दुनियाभर में नास्तिकता बढ़ रही है। कैलिफ़ोर्निया में क्लेरमोंट के पिटज़र कॉलेज में सामाजिक विज्ञान के प्रोफ़ेसर फिल ज़करमैन कहते हैं, "इस समय दुनिया में पहले के मुक़ाबले नास्तिकों की संख्या बढ़ी है।

Death is not just a number say women in Ukraine

Amitabh Srivastava

The war in Ukraine is affecting its ordinary citizens in two ways. One, they are donning the war uniform to fight for their country and secondly, they are turning poets and fighting to give dignity and meaning to the lives lost. Ms. Iryna Tsybukh, a combat medic, educationist and journalist, who died before she could be 26 this May even decided how her own funeral and that of other martyrs should be organised.

नेहरु के व्यक्तित्व निर्माण में जीवनसंगनी का योगदान

के. विक्रम राव

जब मोतीलाल नेहरू ने अपने छब्बीस-वर्षीय पुत्र जवाहरलाल नेहरू की शादी सोलह बरस की कमला कौल (7 फरवरी 1916) से की थी, तब उसकी तह में एक दैवी कारण था। भाई वंशीधर नेहरू, जो ज्योतिषी थे, की राय में पुरानी दिल्ली के सीताराम बाजार मे जन्मी इस कश्मीरी कन्या के वंशजों को राजयोग बदा था, (पृष्ठ-66, ''नेहरू डाइनेस्टी'', वाणी प्रकाशन, लेखक के. एन.रावः कमला नेहरू की कुण्डली)।

Role of Muslims in freedom movement highlighted

Anwarul Haq Baig

A seminar titled "Making of Modern India and Role of Muslims in Freedom Movement" was held on Sunday as part of a year-long campaign by the Jamaat-e-Islami Hind (JIH), Delhi unit, aiming to shed light on the crucial yet often overlooked contributions of Muslims to India's struggle for independence.

एक चाट वाले का फिलसफा और जिंदगी की सच्चाई

अनूप श्रीवास्तव

एक चाट वाला था। जब भी उसके पास चाट खाने जाओ तो ऐसा लगता कि वह हमारा ही रास्ता देख रहा हो। हर विषय पर बात करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। कई बार उसे कहा कि भाई देर हो जाती है, जल्दी चाट लगा दिया करो पर उसकी बात ख़त्म ही नहीं होती

Bangladesh Violence : Misinformation Campaign By Hate Lobby in India

Prof Ram Punivani

Recent events in Bangladesh have led to a significant upheaval, highlighting the country's internal tensions and sparking a wave of fake news and Islamophobia in neighbouring India. Sheikh Hasina, who has ruled Bangladesh with a firm hand for the past fifteen years, has faced criticism for her authoritarian approach, particularly her suppression of opposition voices. Major opposition leaders have been imprisoned or placed under house arrest, leaving little room for dissent.

Visit Our Bilingual Website : www.mediamap.co.in

Subscribe To Our Yourtube Channel : Media Map News

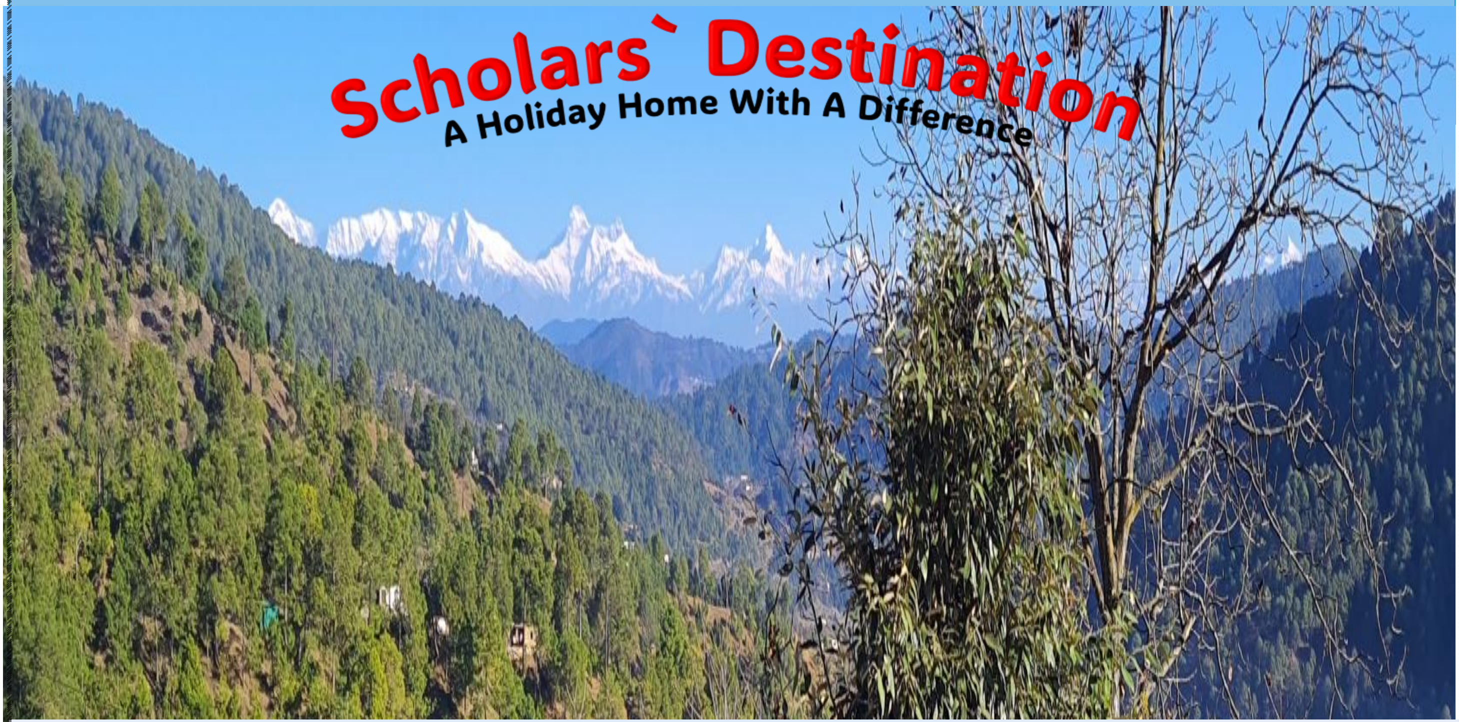

Gehna, Mukteshwar Dham, Nainital

Please Contact

90450 05700 | 99103 22682 | Www.Sdmotel.Com | Info@Sdmotel.Com

RNI No. : UPHIN/2016/68336

BHAGYAM ARTS AND IDEAS

ReflectSeries

A colourful Dance Drama celebrating the life and ideals of Mahatma Gandhi

BHARATANATYAM . DRAMA . KATHAKALI
KATHPUTLI . KATHAK . PANTOMIME

Friday, 27 September 2024, 7.30pm

Jawahar Bhawan, Dr Rajendra Prasad Road, New Delhi - 01

Entry is free. Contact: speak2bai@gmail.com